

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 87 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरुवार, 30 सितम्बर 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

पहली बार एक साथ 75 डाक टिकट किए जारी

लखनऊ (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'एक जिला, एक उत्साह' (ओडीओपी) के नाम बुधवार को एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दुनिया में पहली बार डाक विभाग ने एक साथ ओडीओपी के 75 उत्साहों पर आधारित डाक टिकट जारी किए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड दुनिया में 32 डाक टिकट का ही है। इस पहल से अब ओडीओपी की ब्रांडिंग वैश्विक स्तर पर और देश में भी मजबूत होगी। इससे प्रदेश के परंपरागत उत्साहों को नई पहचान मिलेगी। श्री योगी ने प्रदेश में पहली बार परंपरागत उत्साहों को नई पहचान देने के लिए ओडीओपी की शुरुआत 2017 में की थी।

टीएमसी में आए गोवा के पूर्व सीएम फ्लेरियो

कोलकाता, (एजेंसी) गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और लुइजिन्हो फ्लेरियो ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम व टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात की है। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फ्लेरियो बुधवार को राज्य सचिवालय नवरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम ममता से मुलाकात की। इसके बाद वे टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक लुइजिन्हो फ्लेरियो ने कहा कि आज मैं टीएमसी में शामिल हो गया हूँ। मेरा सपना कांग्रेस परिवार को एक साथ लाने का है। टीएमसी में शामिल होने के पीछे मेरा मुख्य मिशन बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों, नफरत व प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को हराना है।

असम में बंद पेपर मिल कर्मचारियों को वेतन

गुवाहाटी, (एजेंसी) असम में बंद हो चुकी दो पेपर मिलों के वेतन का लंबित मामला आखिरकार सुलझा लिया गया है और इन कर्मचारियों को 55 महीने का वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार तड़के ट्वीट किया कि आखिरकार हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन और बकाया के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौता हुआ है। गुवाहाटी में श्री सरमा के कार्यालय में पेपर मिलों की यूनियनों के साथ हुई बैठक चार घंटे से अधिक समय तक चली और बुधवार तड़के समाप्त हुई।

मुंबारकपुर में डायरिया से 50 से अधिक बीमार

आनमढ़, (एजेंसी) जिले के मुंबारकपुर कस्बे में डायरिया की चोट में आने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गये, जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि मुंबारकपुर कस्बे के में पिछले तीन-चार दिन में इकट्ठा दुकान डायरिया के मरीजों का पता चला था, लेकिन मंगलवार रात अज्ञातकारण डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने से खलबली मच गई है। उन्होंने बताया कि बलुआ मोहल्ले के करीब चार दर्जन लोग डायरिया प्रभावित हैं और उनका सीएचसी मुंबारकपुर में इलाज चल रहा है।

भाजपा ने सिद्धारमेया को आतंकवादी कहा

मंगलूरु, (एजेंसी) कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमेया को आतंकवादी करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं खुद यह महसूस करता हूँ कि वह आतंकवादी है और वह इस तरह के बयान उद्धरण दे रहे हैं क्योंकि वह कांग्रेस में बहुत दयनीय स्थिति में हैं। श्री कतील ने कहा कि सिद्धारमेया की संस्कृति तालिबानी है और उनका कार्यकाल में सबसे अधिक हत्याएं हुई थी। श्री कतील श्री सिद्धारमेया के उस बयान पर प्रतिक्रिया कर रहे थे जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं को तालिबानी कह दिया था।

गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फ्लेरियो टीएमसी में हुए शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी) गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व विधायक नेता लुइजिन्हो फ्लेरियो टीएमसी में शामिल हो गये। कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में टीएमसी में लुइजिन्हो फ्लेरियो के साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी लवू ममलेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एन शिवदास और पर्यावरणविद् राजेंद्र शिवाजी काकोडकर सहित 10 नेता शामिल हुए। इसके पहले वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस अवसर पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित थे।

वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, पंजाब कांग्रेस के संकट से आइएसआइ और पाकिस्तान को फायदा

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी में मंची उथल-पुथल के बीच वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं आपसे (मीडिया) उन कांग्रेसियों की ओर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में पत्र लिखा था। केंद्रीय अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय चुनाव समिति के पद के चुनाव के संबंध में हमारे नेतृत्व द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि ये निर्णय कौन ले रहा है। हम जानते हैं और फिर भी हम नहीं जानते।

पंजाब कांग्रेस के संकट पर उन्होंने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य

(पंजाब) जहां कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इससे आइएसआइ (ट्रस्ट) और पाकिस्तान को फायदा है। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एकजुट रहें। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता से चर्चा करें।

उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए तुरंत सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस को ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं। सोचना होगा कांग्रेस कैसे आगे बढ़े। हमारे लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये है कि लोग पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने कहा कि हम



जी-23 है, जो हुजूर नहीं। हम विडंबना है। जो उनके (पार्टी (जी-23 के नेता) वे नहीं हैं, जो नेतृत्व) करीब थे, वे चले गए। पार्टी छोड़कर कहीं और जाएंगे। यह जिन्हें वे अपने करीब नहीं मानते, वे

अब भी उनके साथ खड़े हैं। जो कांग्रेस के लोग हमें छोड़कर चले गए हैं वो वापस आ जाए क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी विचारधारा है जो इस देश की बुनियाद है जिसके आधार पर हमारी रिपब्लिक बनी थी उसको बरकरार कर सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि संसद जब चलती है तो कई मुद्दों पर चर्चा होती है, मुझे तभी उठे जब विपक्ष मजबूत होगा और विपक्ष तभी मजबूत होगा, जब कांग्रेस मजबूत होगी, अगर ये सब नहीं होगा तो सवाल कैसे पूछ जाएगा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष

तिवारी ने कहा कि पंजाब में जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर पंजाब की अस्थिरता पर किसी को खुरशी है तो वो पाकिस्तान को है।

उनको लगता है कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देने का एक और मौका मिलेगा। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है। पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की जरूरत है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोहाली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

यहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी समस्याएं लेकर कहां जाएं। इन लोगों ने सरकार को तमाशा बना दिया है। अब, ब्रह्म आम आदमी पार्टी) ही पंजाब को एक स्थिर, अच्छी और ईमानदार सरकार दे सकती है। विधानसभा चुनाव में केवल 4 महीने रह गए हैं। 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे तब, कर्पणजब में स्थिर और ईमानदार सरकार देगी।

केंद्र सरकार का फैसला, 1.31 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च

अब पीएम पोषण योजना के नाम से बंटेगा मध्याह्न भोजन

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें केंद्र की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। जिससे स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा ये योजना 5 साल तक चलेगी। अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि अभी जो मिड-डे मील की योजना चल रही है, उसे पीएम-पोषण योजना में ही शामिल किया



कैबिनेट के अहम फैसले

जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि योजना में सुधार किया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय इसकी पूरी जानकारी देगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र ही होगी। इस स्कीम के तहत 54 हजार करोड़ केंद्र और करीब 32 हजार करोड़ राज्य सरकारें खर्च करेंगी।

मध्यप्रदेश, गुजरात की दो रेललाइनों का होगा दोहराकरण

नई दिल्ली, (एजेंसी) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश और गुजरात की दो महत्वपूर्ण रेल लाइनों के दोहराकरण करने को बुधवार को स्वीकृति दी जिस पर दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत आयेगी और यह काम तीन साल में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश में रतलाम - नीमच 132.92 किलोमीटर की लाइन के दोहराकरण का निर्णय लिया गया है जिसपर 1095.88 से 1184.67 करोड़ रुपए के बीच लागत आएगी। इससे आसपास के क्षेत्रों में सीमेंट, टैक्सटाइल उद्योगों के साथ पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। वर्तमान में इस लाइन पर यातायात दबाव 145 फीसदी से अधिक है। दोहराकरण के बाद रेलवे को इस मार्ग से माल ढुलाई में 5.67 से 9.45 टन प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है। श्री ठाकुर ने कहा कि गुजरात में राजकोट कानापुर 111.20 किलोमीटर की रेल मार्ग का भी दोहराकरण करने का फैसला किया गया है जिस पर 1080.58 से 1168.13 करोड़ के बीच लागत आने का अनुमान है। इससे द्वारका ओखा पोरबंदर में रेल यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इस लाइन पर वर्तमान में 157 प्रतिशत से अधिक यातायात दबाव है। इससे सौराष्ट्र क्षेत्र में मालवहन एवं यात्री गाड़ियों के आवागमन को आसान बनाया जा सकेगा।

रतलाम-नीमच 132.92 किमी की लाइन का दोहराकरण

ईसीजीसी के आईपीओ को दी मंजूरी, 4,400 करोड़ का पूंजी निवेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआरए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। वहीं, वाणिज्य मंत्री प्रीतिपा गौतम ने कहा कि भारत को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक उपकरण (आईपीओ) के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक 5 वर्षों में 4,400 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपए तत्काल डाले जाएंगे। कंपनी अगले साल स्वीकृति हो सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का था।



देश की 25 फीसदी जनता को नौसेना और वायुसेना के 13,165 करोड़ के प्रस्तावों को डीएसी ने दी स्वीकृति

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत में कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर देश की 25 प्रतिशत जनता को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं जल्द ही देश में एक नई वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने अनुमानित युवा आबादी के 25 फीसदी लोगों को

वैक्सीन की दोनों डोज दे दी है। बुधवार को 24 घंटे में 54 लाख 13 हजार से अधिक वैक्सीन लगाए गए, जिससे कुल संख्या 87.66 करोड़ हो गई। वहीं, उम्मीद जलाई जा रही है कि कोरोना की एक और वैक्सीन 2 अक्टूबर को मिल सकती है। इसके रेट और अन्य चीजों को लेकर वार्ता की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। 24 घंटे में 18,870 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं और स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.83 प्रतिशत है।

रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को थल सेना, नौसेना और वायु सेना के 13,165 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को एओएन प्रदान किया, जिसमें से 87 फीसदी भेज इंडिया होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी डिजाइन और गोला-बारूद के विकास को बढ़ावा देते हुए, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने लगभग 4,962 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे (भारतीय-



भारत और मेक इन इंडिया की ओर निरंतर जोर देते हुए डीएसी ने बाय इंडियन-आईडीडीएम के तहत एचएएल से लगभग 25 एएलएच मार्क-3 हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 3,850 करोड़ रुपए है।

आईडीडीएम) श्रेणी के तहत टर्मिनली गाइडेड मुनिशन (टीजीएम) और एचईपीएफ/आर एचई रॉकेट गोला-बारूद की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने बाय इंडियन-आईडीडीएम के तहत एचएएल से लगभग 25 एएलएच मार्क-3 हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 3,850 करोड़ रुपए है।

18 लाख की ठगी, 70 साल की महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली ■ एजेंसी

दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के एक केस में अमेरिका भेजने के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी की आरोपी 70 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वह 13 वर्षों से फरार थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एपीसी आरके सिंह ने बताया कि आरोपी कुलविंदर कौर को दिल्ली में चांदनी चौक क्षेत्र से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वह पंजाब के गुरुदासपुर की

निवासी है। पुलिस दल ने एक सूचना के आधार छापेमारी कर गिरफ्तार किया। मानव तस्करी के इस मामले के आरोपियों में शामिल अनिल कुमार एवं लाल चंद को 2010 में ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के गुरुदासपुर निवासी पीडित अमरजीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि 2006 में जागीर सिंह, कुलविंदर सिंह और कुलदीप सिंह ने दिल्ली के अपने सहयोगी एजेंट के साथ मिलकर 18 लाख रुपए की ठगी की।

अमृत महोत्सव श्रृंखला #16



#AmritMahotsav

'कामागाटा मारू' घटना

29 सितंबर 1914



अप्रैल 1914 में, बाबा गुरदित्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्रियों के साथ एक जापानी समुद्री जहाज 'कामागाटा मारू' हांगकांग से रवाना हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को कनाडा के वैंकूवर में उतरने नहीं दिया। मजबूरी में वापस लौटा 'कामागाटा मारू' सितंबर में कलकत्ता के बजबज पर पहुंचा। वहां 29 सितंबर 1914 को पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 19 यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई। 'कामागाटा मारू' घटना ने गदर आंदोलन के उदय में उत्प्रेरक का काम किया।



@BOC_MIB

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार



BOC_MIB

29 सितंबर यानी आज ही के दिन 1914 में ऐतिहासिक कामागाटा मारू घटना हुई थी जिसने भारत की स्वाधीनता के चर्चित गदर आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी।

अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे अमरिंदर सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर 45 मिनट मुलाकात की।

कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच किसानों के कृषि कानूनों के मुद्दे पर कई बातें साफ हुई हैं जिसका ब्लू प्रिंट तैयार करने को लेकर सहमति बनी है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने आने वाली धान की फसल को लेकर शाह से किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने



कृषि कानून के ब्लू प्रिंट पर हुई बात

वे एक बार फिर केंद्रीय मंत्री शाह से मुलाकात करेंगे।

देने का आग्रह किया है। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने जल्दी ही सीसी लिमिटेड पंजाब के लिए रिटायर करने की बात की जिससे किसानों को पेमेंट के लिए कोई दिक्कत न आए और फसल मंडियों से आसानी से उठ जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जल्दी ही दूसरी बैठक होगी और इसके साथ फाइनल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में होगी। सूत्र बताते हैं कि

20 हजार रुपए देकर आतंकी को भेजा भारत

नई दिल्ली ■ एजेंसी

जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुई मुठभेड़ के दौरान सेना द्वारा पकड़े गए एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने सीमापार स्थित अपने आकाओं से कहा है कि उसे उसकी मां के पास पहुंचा दिया जाए।

पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर पात्रा ने सेना द्वारा बुधवार को यहां जारी किये गए एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं लश्कर ए तैयबा के एरिया कमांडर, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से अपील करता हूँ कि वे मुझे उसी तरह मेरी मां के पास वापस भेज दें जैसे उन्होंने मुझे यहां (भारत) भेजा। सेना ने 26 सितंबर को उरी में मुठभेड़ के दौरान पात्रा को पकड़ा था। उस समय वह अपने जान की भीख मांग रहा था। सेना का अभियान 18 सितंबर को शुरू हुआ था और नौ दिन तक चला था जिसमें एक अन्य पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया था।

वीडियो संदेश में अली बाबर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर ए तैयबा कश्मीर के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उसने कहा कि हमें बताया गया कि भारतीय सेना रक्त बहा रही है लेकिन यहां सब शांतिपूर्ण है। मैं अपनी मां को बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया।



पैसों की तंगी के चलते लश्कर में भर्ती हुआ था

खुद के आतंकी समूह में शामिल होने के बारे में बताते हुए पात्रा ने कहा कि उसके पिता की सात साल पहले मौत हो गई थी और पैसों की कमी के चलते उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। उसने कहा कि मैंने सियालकोट की एक कापड़े की फैक्ट्री में नौकरी की जहां मैं अनस से मिला जो लश्कर ए तैयबा के लिए लोगों की भर्ती करता था। मेरी हालत के कारण मैं उसके साथ चला गया। उसने मुझे 20 हजार रुपये दिए और बाद में 30 हजार और देने का वादा किया। पात्रा ने यह भी बताया कि खैबर दलीहबीबुल्ला शिद्वि में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उसे किस तरह के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया।

सार समाचार

भारत के इस कदम को अमेरिकी सांसद ने की सराहना, हिंद-प्रशांत और दुनिया के लिए बताया अहम कदम

वाशिंगटन। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जिम रिश ने कोविड-19 रोधी टीकों का निर्यात पुनः शुरू करने के भारत के निर्णय की सराहना की है। सीनेटर की विदेश मामलों की समिति के 'रैकिंग' सदस्य रिश ने भारत से अपील भी की कि वह इन टीकों का उत्पादन बढ़ाए, ताकि उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ पूरी हो सकें। रिश ने ट्वीट किया, ' मैं भारत की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ कि वह कोविड-19 रोधी टीकों का निर्यात पुनः शुरू करेगा।' उन्होंने कहा, ' मैं भारत को 'कोविड' के और अन्य वाणिज्यिक ऑर्डर पूरे करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जो पूरे हिंद-प्रशांत और दुनिया के लिए अहम है।

जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में ईंधन संकट में सुधार आ रहा है

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को ब्रिटेन की जनता को आश्वासन देने की कोशिश करते हुए कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि उनकी सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। जॉनसन की सरकार ने गैसोलीन का वितरण करने और ईंधन की कमी को कम करने में मदद करने के लिए सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। यह संकट टुक चालकों की कमी की वजह से उत्पन्न हुआ है और सैकड़ों ईंधन स्टेशनों में गैस खत्म हो गई। लोगों को गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। जॉनसन ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, 'अब हम स्थिति में सुधार देख रहे हैं। स्थिति स्थिर हो रही है, लोगों को आश्वासन होना चाहिए और सामान्य तरीके से अपने व्यवसाय पर जाना चाहिए।' फ्रंटलिन रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी कहा कि इस बात के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि ईंधन संकट समाप्त हो रहा है।

फुमियो किशिदा ने जापान को सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की

टोक्यो। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के फुमियो किशिदा ने बुधवार को जापान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। समाचार एजेंसी ने सुचना दी कि एलडीपी के नेतृत्व वाला गढ़बन्धन जापान में संसद के दोनों सदनों में बहुमत का गठन करता है। नए पार्टी अध्यक्ष का 4 अक्टूबर को होने वाले असाधारण सत्र में प्रधानमंत्री चुने जाना लगभग निश्चित है, जो कि मौजूदा योशीहिदे सुगा के उत्तराधिकारी हैं।

अमेरिकी सीनेटरों ने तालिबान की जीत में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की

नई दिल्ली। रिपब्लिकन सीनेटरों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान की जीत और अशरफ गनी के नेतृत्व वाले शासन को खदेड़ने में मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर गहरी जांच की मांग की गई है। जियो टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि विधेयक (बिल) 2001 और 2020 के बीच तालिबान के लिए पाकिस्तान सरकार सहित राष्ट्र और गैर-राष्ट्र एजेंट्स द्वारा समर्थन, अभयारण्य स्थान, वित्तीय सहायता, खुफिया सहायता, रसद और वित्तिसा सहायता, प्रशिक्षण, उपकरण, सामरिक, परिवहन या रणनीतिक दिशा आदि के प्रावधान का मूल्यांकन चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान काउंटर टैरिस्ट, एंड एकाउंटैबिलिटी एक्ट एक टारगट फोर्स की स्थापना करना चाहता है, जो अमेरिकी नागरिकों, कानूनी स्थायी निवासियों और अफगानिस्तान से विशेष अप्रवासी वीजा धारकों की निरंतर निकासी पर ध्यान केंद्रित करेगा। 22 अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा पेश किया गया, बिल अफगान वापसी से संबंधित मुद्दों से निपटने का प्रयास करने के लिए है, जैसे कि आतंकवाद विरोधी रणनीति और देश में कथित मानवाधिकारों के हनन के लिए तालिबान को मंजूरी देना।

जापान की एलडीपी नेतृत्व की दौड़ जीतने के बाद किशिदा ने एकजुट होने का किया आह्वान

टोक्यो। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के चुनाव जीतने के बाद फुमियो किशिदा ने बुधवार को प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा को जगह ली और एलडीपी की एकजुटता का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2012 से 2017 तक देश के पूर्व विदेश मंत्री के रूप में कार्य करने वाले किशिदा ने अपने दावेदार बेकसीन मंत्री तारो कोनो पर जीत हासिल करने के लिए 257 वोट हासिल किए, जबकि उन्हें 170 वोट मिले। चुनाव के बाद एलडीपी सांसदों की एक बैठक में, किशिदा ने एकजुटता का आह्वान किया है, क्योंकि वह नवंबर में होने वाले आम चुनाव और अगले साल ऊपरी सदन के पार्षदों के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। किशिदा ने कहा कि उनकी सरकार को कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजों को कम करने के लिए साल के अंत से पहले एक योजना तैयार करने चाहिए। उन्होंने पिछले प्रशासन की नवउदारवादी नीतियों को बदलने का भी वादा किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आम लोग विकास का लाभ उठा सकें। दोपहर में राष्ट्रपति चुनाव में, एलडीपी सांसदों ने पहले दौर के मतदान में 382 वोट डाले और अन्य 382 वोट रैक-एंड-फ्रंट सदस्यों को आवंटित किए गए। एलडीपी सांसदों के वोटों में एक प्रमुख लाभ के साथ, किशिदा को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया। दो महिला उम्मीदवार, पूर्व संघार मंत्री, साने ताकावी और एलडीपी के कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव, सेको नोडा, दोपहर में पहले दौर के मतदान में हार गए थे। चूंकि एलडीपी के नेतृत्व वाला गढ़बन्धन जापान में संसद के दोनों सदनों में बहुमत का गठन करता है।

दक्षिण कोरिया, चीन के राजदूतों ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण पर चर्चा की



सियोल (एजेंसी)।

दक्षिण कोरिया के मुख्य परमाणु वार्ताकार नोह क्यू-डुक ने बुधवार को अपने चीनी समकक्ष के साथ वीडियो वार्ता की और उत्तर कोरिया के नवीनतम मिसाइल प्रक्षेपण और हालिया बयानों पर चर्चा की।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नोह की बातचीत कोरियाई प्रायद्वीप के मामलों पर बीजिंग के विशेष प्रतिनिधि लियू श्याओमिंग के साथ हुई, जिसके एक दिन बाद उत्तर ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पूर्वी सागर में परीक्षण किया। प्योंगयांग ने इंटर-कोरियाई संबंधों में सुधार करने और यहां तक कि सियोल के साथ एक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद ही गोलीबारी की, इस शर्त पर कि दक्षिण शासन के खिलाफ अपने दोहरे मापदंड और शत्रुतापूर्ण रवैये को

छेड़ देगा।

मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में वार्ता के दौरान कहा, नोह ने प्योंगयांग को वार्ता में वापस लाने के प्रयासों में चीन की रचनात्मक भूमिका के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने प्रायद्वीप की स्थिति के स्थिर प्रबंधन और वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। मंत्रालय के अनुसार, लियू ने कोरियाई प्रायद्वीप के लिए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए बीजिंग की इच्छा की पुष्टि की। दोनों ने चर्चा जारी रखने के लिए जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से मिलने पर भी सहमत जताई। मंगलवार को नोह ने अपने अमेरिकी समकक्ष सुंग किम से भी फोन पर बात की और उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण पर चर्चा की। नोह गुरुवार को किम के साथ बातचीत के लिए दिन में बाद में इंडोनेशिया के लिए रवाना होने वाले हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है : श्रृंगला



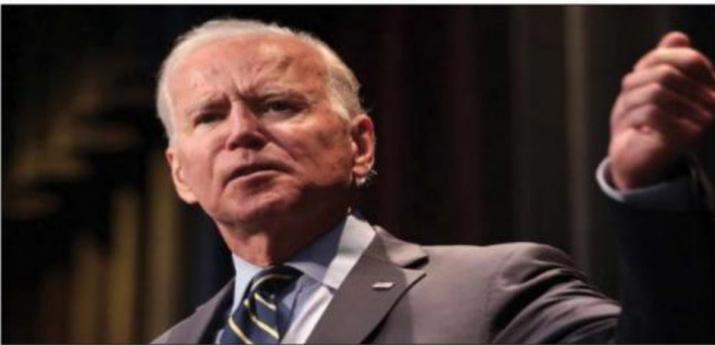
नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को पहले परमाणु हथियार उपयोग नहीं करने और गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं करने के अपने सिद्धांत की पुष्टि की और संयुक्त राष्ट्र को बताया कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और एक सहमत बहुपक्षीय ढांचे के जरिए हासिल किया जा सकता है जोकि वैश्विक और गैर-भेदभावपूर्ण है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का स्वागत करता है। श्रृंगला ने कहा, भारत सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन हो सके।

अफगानिस्तान में 2,500 बलों को मौजूद रखे जाने की थी सिफारिश, क्यों नहीं माने जो बाइडेन?

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

शीर्ष अमेरिकी जनरलों ने सांसदों को मंगलवार को बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में 2,500 बलों को मौजूद रखे जाने की सिफारिश की थी, लेकिन देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहमत नहीं हुए। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के इस फैसले का बचाव किया और स्वीकार किया कि इस मामले को लेकर बाइडेन के सलाहकारों एवं जनरलों के बीच दोरार्य थीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टॉफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले और यूएस सेंट्रल कमान के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेजी ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को बताया कि पेंटागन ने अफगानिस्तान से बलों की वापसी के बाद भी वहां 2,500 अमेरिकी सैनिकों को रखने की आवश्यकता के बारे में बाइडेन से सिफारिश की थी। मैकेजी ने सीनेटरों से कहा, ' मैं आपको अपनी राय इमानदारी से दूंगा और मेरी राय एवं विचारों ने ही मेरी सिफारिश को आकार दिया। मैंने सिफारिश की थी कि हम अफगानिस्तान में 2,500 बलों को मौजूद रखें और मैंने 2020 में भी सिफारिश की थी कि हम उस समय 4,500 बलों को मौजूद रखें। ये मेरी निजी विचार थे।' मिले ने सांसदों से कहा कि वह भी अफगानिस्तान में 2,500 बलों को तैनात रखने की सिफारिश से सहमत थे।

सीनेटरों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की



वापसी के तरीके को लेकर पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व से जब सवाल किए, तो ऑस्टिन ने कहा, 'उनकी (अमेरिकी जनरलों की) बात पर राष्ट्रपति ने गौर किया था।' उन्होंने कहा, ' मैं संतुष्ट हूँ कि हमने नीति की पूर्ण समीक्षा की थी और मेरा मानना है कि सभी पक्षों को अपने विचार रखने का अवसर दिया गया था।' व्हाइट हाउस ने इस संबंध में राष्ट्रपति के फैसले का बचाव किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ' इस मामले में कई तरह के दृष्टिकोण थे, जैसा कि आज हमें उनकी गवाही से पता भी चला। ये विचार राष्ट्रपति

और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के समक्ष रखे गए थे। राष्ट्रपति ने ही उनसे अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने को कहा था।' उन्होंने कहा, ' यह भी स्पष्ट था कि यह सिफारिश दीर्घकाल के लिए नहीं थी और बलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती। इसका यह भी अर्थ होता कि तालिबान के साथ युद्ध होता और इससे बड़ी संख्या में लोग होताहत होते। राष्ट्रपति ऐसा फैसला नहीं करना चाहते थे।' प्रेस सचिव ने कहा, ' उन्हें नहीं लगा कि यह अमेरिकी लोगों या हमारे बलों के हित में होता।

पड़ोसी की जान लेने पर उतारू हुई महिला! गुस्से में पावर ब्लैकआउट अब बीजिंग और शंघाई में शुरु पहले दो उंगलियां दांतों से चबाई फिर खा गईं

नई दिल्ली (एजेंसी)।



जब इंसान को गुस्सा आता है तो वह अपने होशोहवास तक खो देता है। गुस्से में इंसान मारपीट की कगार तक भी पहुंच जाता है और नुकसान तक पहुंचता है। ऐसा ही कुछ स्पेन की एक महिला ने किया है। इस महिला ने गुस्से में आकर अपनी ही पड़ोसी की दो उंगलियां चबा डालीं। एक खबर के मुताबिक, स्पेन में दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई में एक महिला अपने पड़ोसी से इतनी ज्यादा नाराज थी कि गुस्से में आकर उसने उंगलियां चबा डालीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मामला भी दर्ज कर दिया है। यह लड़ाई बस इस बात पर हुई कि महिला को शक था कि उसकी पड़ोसी जादू-टोना करती है।

इसको लेकर दोनों के बीच बहस हुई फिर हाथपाई शुरू हो गई। दस की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के स्ट्रिडघट्टर में रहने वाली 45 साल की महिला को 48 वर्षीय पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जादू-टोना का था पड़ोसी को शक आरोपी ने दांतों से दो उंगलियां पहले चबाई फिर उसे खा गईं। इस पूरी वारदात

को खुद आरोपी की 6 साल की बेटी ने अपनी ही आंखों से देखा। पुलिस को इसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने दिया। पुलिस ने बताया कि, जब वह मौके पर पहुंची तो पाया कि आरोपी ने पीठवरी कर बहुत बुरी तरह पिटाई की थी। पुलिस ने आगे बताया कि, पड़ोसी को शक था की महिला जादू-टोना करती थी और पानी में नमक मिलाकर उसके घर पर छिड़कती थी। इसी बात को लेकर दोनों की बीच बहस-बहसी हुई और फिर भारी पत्थर से वार किया। महिला यहीं नहीं रुकी, इसके बाद आरोपित महिला ने गुस्से में दो उंगलियां अपने दांतों से काटी और उन्हें खा गईं। इस समय पीठवरी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं आरोपी महिला को मानसिक स्थिति के लिए जांच में भेजा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

चीन ने अब बीजिंग और शंघाई में ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया है, जहां 48 मिलियन लोग रहते हैं, क्योंकि देश बिजली की कमी से जूझ रहा है, जिसने अर्थव्यवस्था के लिए एक और खतरे में प्रमुख कारखानों को प्रभावित किया है। इसकी जानकारी निक्केई ने दी। स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के बीजिंग कार्यालय ने कहा कि वह रविवार से चुनिंदा क्षेत्रों में बिजली की कटौती शुरू कर देगा। बिजली मुख्य रूप से एक बार में कुछ दिनों के घंटों के लिए काटी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि रोलिंग ब्लैकआउट से राजधानी के कम से कम चार जिले प्रभावित होंगे। इनमें जिंग्चेंग और डोंगचेंग शामिल हैं, जिनमें सरकारी एजेंसियां और शीर्ष अधिकारियों का आवास है, चाओयांग, जहां कई विदेशी रहते हैं और हैडन, जहां कई तकनीकी कंपनियां स्थित हैं। स्टेट ग्रिड ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुख्य उद्देश्य नियमित उपकरण रखरखाव और पावर ग्रिड में अपग्रेड करना है। वर्तमान में, राजधानी में पावर ग्रिड में पर्याप्त, स्थिर और व्यवस्थित आपूर्ति है।

प्रभावित घरों और व्यवसायों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि ब्लैकआउट लगभग 60 ग्रिड सेक्शन में कटौती करते हैं, जिससे 10,000 से अधिक लोग बिना बिजली के रह जाएंगे। बीजिंग की आबादी 22 मिलियन है। अनुसूचित ब्लैकआउट मुख्य रूप से निजी आवासों को लक्षित करते हैं, बड़े पैमाने पर कारखानों को बचाने के लिए। शंघाई, रिवार को भी रोलिंग ब्लैकआउट का संचालन करेगा। राष्ट्रीय बिजली की कमी ने एप्पल और टेस्ला के आपूर्तिकर्ताओं को शंघाई से स्टेट जिआंग्सु प्रांत में परिवर्तन को निर्लंबित करने का कारण बना दिया है। निक्केई ने कहा कि ग्वांगडोंग प्रांत में जापानी निर्माताओं द्वारा संचालित फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं। बिजली की किल्लत का खामियाखाना पूर्वोत्तर में चीन का मुक्त बेल्ट क्षेत्र उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लियाओनिंग प्रांत के एक शहर शेनयांग में ट्रैफिक सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे भीड़भाड़ हो गई है। जिलिन प्रांत में, जिलिन सिटी की पानी की आपूर्ति अस्थिर रही है और अधिकारियों ने नागरिकों से पानी का स्टॉक करने का आह्वान किया है।

यूरोपीय देशों में रफता-रफता रफतार पकड़ती सेंटर-लेफ्ट पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में भी दिखेगा बदलाव?

इंदौर। (एजेंसी)।

लंबे वक्त से धरातल पर जा रही राजनीति की एक शैली हालिया कुछ दिनों में छोड़ी राहत महसूस कर रही है। इसके साथ ही उन्हें संभावित वापसी की आस भी जग रही है। 21वीं सदी में पश्चिमी देशों में रूढ़िवादिता, और दक्षिणपंथियों से इतर सेंटर-लेफ्ट पॉलिटिक्स का उभार देखा जाने लगा है। इस महीने सेंटर-लेफ्ट दलों ने नॉर्वे में सत्ता संभाली है और जर्मनी में भी ऐसा ही करने की कगार पर हैं।

इसके साथ ही अमेरिका के व्हाइट हाउस पर उनका कब्जा है ही इसके अलावा इटली में भी सत्ता सौंपेदार के रूप में मौजूदगी देखी जा सकती है। सत्तावादी झुकाव वाले हंगरी में विपक्षी आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे सेंटर लेफ्ट नीत राजनीति की वापसी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसे हाल के दिनों में संपन्न कनाडा और जर्मनी के चुनाव के संदर्भ से जोड़ कर देखें तो एक तरह का बदलाव या उसकी आहट साफ नजर

आएगी।

यूरोपीय देशों में रफता-रफता रफतार पकड़ती राजनीति

जर्मनी की केंद्र-वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) ने मौजूदा कुलपति ओलाफ स्कॉलज के नेतृत्व में संघीय चुनावों में लगभग 26 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, जो एक नई सरकार की शुरुआत कर सकता है और एंजेला मर्केल युग के अंत का प्रतीक होगा। वहीं कनाडा के लिबरल नेता प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से चुनावी जीत हासिल कर ली। अल्पमत में होने के बावजूद ट्रूडो की लिबरल पार्टी को लेफ्ट की तरफ झुकाव रखने वाले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे दलों से नीतियों के आधार पर समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सेंटर लेफ्ट पार्टियां इटली और स्पेन में गठबंधन सरकारों का नेतृत्व कर रही हैं और हंगरी में एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में हैं।

पॉपुलिज्म से मोहभंग की वजह

कोविड ने यूरोप की दक्षिणपंथी पार्टियों को सत्ता से दूर रखने में बड़ी भूमिक निभाई।

अधिकांश ने महामारी के दौरान समर्थन में गिरावट दर्ज की। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में कैस मुडे और जैकब वॉडेंस के एक अध्ययन के अनुसार यूरोप के आधे दक्षिणपंथी दलों ने महामारी के तहत अपने समर्थन में गिरावट देखी, जबकि छह में से केवल एक को समर्थन मिला। यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के एक विद्वान विटोरियो बुफाची का मानना है कि कोविड-19 ने पॉपुलिज्म राजनीति की परतें खोल दीं। पश्चिमी देशों पर नजर डालें तो इसे अमेरिका और ब्राजील के संदर्भ में समझ सकते हैं। लॉकडाउन विरोधी और टीका विरोधी भावनाओं ने इन दोनों देशों में चुनाव में पॉपुलिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वहीं कनाडा के संदर्भ में देखें तो अनिवासी टीकाकरण नीति के वनस्पत करकेविटव का रवैया भी उनके पिछड़ने के एक बड़े कारक के रूप में सामने आया।

लेफ्ट-राइट-सेंटर कॉन्सेप्ट

1789 के साल में फ्रांस की नेशनल एसेंबली के सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के इरादे से एकजुट हुए। 16वें किंग लुई

को कितना अधिकार मिलना चाहिए इसको लेकर सदस्यों के बीच काफी मतभेद था। सदस्य हो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा राजशाही के समर्थकों का था और दूसरा राजशाही के विरोध का। दोनों ने ही अपने बैठने की जगह वांट ली। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य पीठासीन अधिकारी की बायों और बैठ गए जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेंट सदस्य पीठासीन अधिकारी के दायों और बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वुजूद में आया। राजनीतिक पार्टियों ने तो बाद में खुद को 'सेंटर लेफ्ट', 'सेंटर राइट', 'एक्सट्रीम लेफ्ट' और 'एक्सट्रीम राइट' के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया।

लेफ्ट से कांग्रेस में कन्हैया

बिहार में सीपीआई की झंडा बुलंद करने ले कन्हैया कांग्रेस की आवाज बन गए। वैसे तो लेफ्ट से कांग्रेस की ओर रुख करने वाले कन्हैया के कदम को वामपंथी दलों ने सियासी महत्वकांक्षी जरूर बताया है लेकिन उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का



विकल्प चुना है, इसे भी आने वाले वक्त में छोटे स्तर पर ही रही लेकिन एक राजनीतिक शिफ्ट के रूप में देख सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा नहीं है, राज्य में पार्टी अपनी हालत सुधारने के लिए नए चेहरों पर दांव लगाया चाहती है। जानकारों को लगता है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस की योजना राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर दबाव बनाने की भी है जो अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाती रही है।

भाजपा-कांग्रेस ने जनता का भरोसा तोड़ा : सिसोदिया

गुजरात में तीन अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनावों से पहले भरी चुनावी हुंकार

प्रफुल्ल राय(शिवालिक)

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को गांधी नगर, गुजरात में तीन अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनावों से पहले चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने गांधी नगर में रोड शो किया जिसे जबरदस्त जनसमर्थन मिला और हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस रोड शो में भाग लिया।

इस अवसर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने गुजरात की जनता का भरोसा तोड़ उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी गांधी नगर की जनता के समर्थन से गुजरात में बदलाव की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी की सूरत में लोगों से जो भरोसा और विश्वास मिला है, गांधी नगर की जनता भी आप पर यही भरोसा दिखा रही है। आप इस भरोसे के साथ गुजरात में जनता के हितों के काम कर बदलाव की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि गांधी नगर के निकाय चुनाव भाजपा के फेलियर, भाजपा के प्रति जनता के

दृढ़ते विश्वास बनाम आम आदमी पार्टी का जनाधार, सूरत के आप पार्षदों का काम और दिल्ली में आप द्वारा किए गए काम के बीच है और गांधी नगर की जनता आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति को चुनकर अपने वोट की ताकत से गांधी नगर म्युनिसिपल कारपोरेशन की तस्वीर बदलने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में आप पर अपना भरोसा कायम किया था। ठीक वही विश्वास आज गांधी नगर की जनता दिखा रही है। उन्होंने कहा कि आज लोगों का भाजपा से विश्वास उठ चुका है और लोगों ने कई बार भाजपा के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर कांग्रेस को चुना लेकिन कांग्रेस ने भी गांधी नगर की जनता के साथ विश्वासघात और गद्दारी की। जनता के वोट को उनके समर्थन और भरोसे को भाजपा को बेच दिया। इसलिए जनता आज विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी



जनता के समर्थन से गुजरात में बदलाव की शुरुआत करेगी पार्टी : सिसोदिया

को देख रही है और उस पर भरोसा जता रही है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली में जैसे बदलाव हुए हैं, गुजरात की जनता भी वैसे बदलाव चाहती है। सूरत के निकाय चुनावों में आप को मिला जनसमर्थन इसका उदाहरण है। पहली बार में ही सूरत में आप को 27 सीटें मिली ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जमीन पर

दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पूरे विश्व में होती है सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पूरे विश्व में चर्चा होती है। ये एजुकेशन मॉडल गुजरात में भी अपनाया जा सकता है। गुजरात के शिक्षक इतने सक्षम है कि वो यहां के एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते है लेकिन यहाँ की सरकार इसके लिए उदासीन है और शिक्षकों को संसाधन नहीं देती है। जब दिल्ली में शिक्षा,स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आ सकता है। जनता को फ्री बिजली-पानी मिल सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं। आप जनता के समर्थन के साथ गुजरात में भी बदलाव लाने का काम करेगी।

उतर कर जनता के लिए काम कर रहे है। पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि पार्षद का असल काम क्या होता है और ईमानदारी से काम करने वाला एक पार्षद मिल जाए तो काम कैसे होता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि तीन अक्टूबर को गांधी नगर में होने वाला निकाय चुनाव भाजपा के फेलियर, भाजपा के प्रति जनता के दृढ़ते विश्वास बनाम आम आदमी पार्टी का जनाधार, सूरत के आप पार्षदों का

काम, दिल्ली में आप द्वारा किए गए काम के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी नगर की जनता के वोटों में इतनी ताकत है कि वो गांधी नगर म्युनिसिपल कारपोरेशन की तस्वीर बदल सकते है। जनता के वोट में इतनी ताकत है कि वे साफ-सफाई से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और म्युनिसिपल कारपोरेशन के दायरे में आने वाले हर चीज को तस्वीर बदल सकते है।

30 सितंबर को एक्सपायर हो रहे डील को लेकर दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली । अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर तक एक्सपायर हो रहा है और परमानेंट लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट की तारीख थोड़ी देरी से मिल रही है तो ऐसे मामलों में दिल्ली में आदमी पार्टी सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट समेत दूसरे सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरी जरूरी दस्तावेज अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा।

यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार ने परिवहन सेवाओं में सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में जौनल दफ्तरों में भीड़भाड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इसके रहत अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस देने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में अधिकतर परिवहन सेवाओं को आनलाइन सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा। इसी कड़ी में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की योजना है, जिसमें कोई भी घर पर किसी भी समय ऑनलाइन टेस्ट दे सकेगे और टेस्ट पास करने के बाद उनको लाइसेंस मिल जाएगा।

दिल्ली सरकार की मानें तो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज समेत दिल्ली विश्वविद्याल के तकरीबन 88 कालेजों में लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई है। यह योजना डीयू के सभी कालेजों के लिए भी होगी और जो भी कालेज इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेगा।

दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने और बेचने पर लगना पूर्ण प्रतिबंध

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का मंगलवार को आदेश दिया. आदेश के मुताबिक, कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेश है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जशन मनाने लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन होगा, बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बनेगा.

आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए, मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. डीपीसीसी ने आदेश में कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. डीपीसीसी ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों पर अमल कराएं और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें.

हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था, पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थि्ति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके.

इसके साथ ही उन्होंने कहा था, पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए दर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें.

दिल्ली/एनसीआर 3

दिल्ली दंगा: जांच अधिकारी ने आरोपित को उपलब्ध नहीं कराई ई-चालान की कापी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। कड़कड़झमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले की जांच कर रहे एक जांच अधिकारी पर आरोपित को ई-चालान की प्रति उपलब्ध न करवाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को ई-चालान की एक प्रति देने का निर्देश दिया था और पुलिस ने प्रति उपलब्ध कराने के बजाय मामला स्थगित करने का अनुरोध कर दिया।

मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गंग ने कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और बहुत ही लापरवाह तरीके से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को इस मामले की जांच करने को भी कहा। कोर्ट ने जुर्माना राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक और जांच अधिकारी तय तारीखों पर केस की सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं होते हैं और जब पेश होते हैं तो फाइल का निरीक्षण किए बिना आते हैं।

उधर दिल्ली सरकार ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट समेत दूसरे सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर से पहले खत्म हो रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए

तालीम और तहजीब के लिए स्कूल खोलेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, सीता रसोई भी खोलने का लक्ष्य

नई दिल्ली । मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) तालीम और तहजीब का मंदिर स्थूल खोलेगा। इसी तरह स्वरोजगार को बढ़ावा देने, भूखों के लिए सीता रसोई, सामूहिक खिाह तथा यतीमखाने खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। इनके अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा भवन में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए। बैठक में हिंदू, मुस्लिम एकता पर विशेष जोर देते हुए देश को प्रगति, शांति, संपन्नता के रास्ते ले जाने का फैसला हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंदरश कुमार ने की। इसमें विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के आरंभ में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसके बाद देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के साथ ही कोरोना महामारी के दौरान जलन गंवाने वाले मंच के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में मंच के प्रकोष्ठों की पुररचना की गई। मीडिया, महिला, युवाइजीवी, युवा, मदरसा शिक्षा, गोसेवा, सेवा व परिवारण जैसे प्रकोष्ठ बनाए गए।

इंद्रश कुमार के मार्गदर्शन में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थूल

दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी दस्तावेज अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा।

दूसरी ओर दिल्ली सरकार ई-आटो को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में आटो रिवशा की संख्या पर एक लाख की सीमा (कैप) को हटाने के पक्ष में है। सरकार इसे लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकती है। मंगलवार को सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्वएम) के साथ चर्चा की गई थी। केंद्रीय पैनल भी इस कदम का समर्थन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आटो के मामले में कैप हटा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग अब तक आटो का 95,000 परमिट जारी कर चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ई-आटो के लिए 4,200 परमिट आरक्षित किए हैं। इसमें 35 फीसद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कैप के अनुरार दिल्ली में अभी कुल एक लाख आटो चल सकते हैं।

संक्षिप्त खबर

हृदय को नुकसान पहुंचा रहा

जंक फूड : डॉ.कालरा



नई दिल्ली । ज्यादा वसा, नमक

और चीनी वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर पैकेट के सामने की

ओर चेतावनी को अनिवार्य

बनाया जाना चाहिए। सरकार

को इस चेतावनी व्यवस्था के

लिए राजी करने के लिए आम लोगों,

अभिभावकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों को एक साथ आना चाहिए। भारत में युवाओं को हृदय रोगों का बढ़ता खतरा टाला जा सकता है, अगर कम उम्र से ही खाने-पीने की चीजों में शामिल अवयवों के बारे में जागरूकता लाई जाए। विश्व हृदय दिवस के मौके पर कीर्ति नगर स्थित कालरा अस्पताल के निदेशक और जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.आर.एन.कालरा

ने कहा कि इस तरह का अस्वास्थ्यकर आहार पूरे शरीर को, खासकर हृदय को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। डॉ. आर एन कालरा ने कहा कि बिना देखे-परखे अनहेल्दी फूड का अनियंत्रित सेवन और भागदौड़ वाली मौजूदा जीवन-शैली दिल पर कहर डब रही है। इस वजह से 4० वर्ष से कम उम्र के युवा भी हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि धमनियों के संकुचित होने की वजह से दिल की बीमारी होती है।

अधिवक्ता परिषद में कार्यकारी अध्यक्ष व महामंत्री की व्यवस्था की गई खत्म

नई दिल्ली । अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष व महामंत्री पद की व्यवस्था को खत्म किए जाने का निर्णय लिया गया। चिंतन बैठक में प्रदेश की दिग्भिनज जनपदों के 1०0 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं की सक्रिय सहभागिता बने इस पर भी मंथन हुआ साथ ही युवा व महिला अधिवक्ताओं को संगठन से जोड़ने पर बल दिया गया। बैठक में क्षेत्र कार्यवाह डा.वीरेन्द्र जायसवाल और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार लाल बहादुर सिंह के सानिध्य में कई निर्णय लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चन्द्र सक्सेना ने प्रदेश भर आए प्रतिनिधियों के समझ डटवाया, औरैया, झारसी, हमीरपुर, महोबा, उरई में नए जिला अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी महामंत्री की व्यवस्था को सर्वसम्मति से समाप्त कर दिया गया।

बिना लाइसेंस के चल रहा रेस्टोरेंट कराया बंद

नई दिल्ली । साड़ी विवाद के बाद चर्चा में आया अकिला रेस्टोरेंट पिछले 2 साल से बिना लाइसेंस के ही चल रहा था। इस दौरान न तो साउथ एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग ने रेस्टोरेंट की जांच की और न ही कोई नोटिस जारी किया। विवाद बढ़ने के बाद जब हड़कंप मच तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस ही नहीं है। बुधवार को हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सदन में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि अकिला रेस्टोरेंट के पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। पिछले दो साल से यह कैसे चल रहा था, इस मामले की जांच होनी चाहिए। महापौर को देखना चाहिए कि इस मामले में कहा चुक हुई है। वहीं इस मामले में महापौर मुकेश सुर्यांव ने कहा कि वह खुद जाकर रेस्टोरेंट का कहरना है कि विवाद के बाद पता चला कि वहां कोई रेस्टोरेंट भी चल रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात 30 वर्षीय जवान ने खुद को मारी गोली, मौत

नई दिल्ली । राजस्थान आर्म्ड में तैनात एक जवान ने दिल्ली उच्च न्यायालय के परिसर में आत्महत्या कर ली. दिल्ली उच्च न्यायालय की सुरक्षा में तैनात 30 वर्षीय जवान ने अपने सक्कारी हथियार से खुद को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक जवान राजस्थान के अलवर से था. कुछ दिनों पहले ही अवकाश खत्म करके अपने घर से लौटा था. पुलिस मामले को पड़ताल कर रही है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर यह जवान ड्यूटी पर तैनात था. जवान का नाम टिंकू राम (3०) है. जवान आरएसी की आठवीं बटालियन में तैनात था. आज सुबह ही वह ड्यूटी पर वापस आया था और 9 बजकर 30 मिनट पर हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर उसकी ड्यूटी लगी थी. आधा घंटे दो गेट नम्बर 3 के पास मौजूद था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने गोली की आवाज सुनी और सभी स्टाफ हकतत में आए. किसी अन्होनी की आशंका की वजह से जांच की गई तो जवान का शव मौके पर मिला, जिसके बाद पुलिस पीसीआर को सवा 10 बजे के आसपास जानकारी मिली तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मामले के गंभीरता को देखते हुए जौन के जॉइंट कमिश्नर जसपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने गेट नंबर 3 के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल की है. साथ ही आरएसी के दूसरे जवान, जो हाईकोर्ट के अंदर ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे मृतक के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई है, ताकि खुदकुशी की वजह का पता लगाया जा सके. हालांकि, पुलिस अभी तक सुसाइड नोट की बात को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन जवान की खुदकुशी के पीछे कोई बड़ी वजह मानी जा रही है. बताया गया कि जनम टिंकू राम कोई दिन से छुट्टियों पर था और अपने गांव गया हुआ था.

गोगी और टिष्ठू गिरोह के बदमाश इंटरनेट मीडिया पर एक दूसरे को इस अंदाज में दे रहे धमकी

नई दिल्ली । कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या के बाद दो खेमों में बंटे गैंगस्टरों के शूटरों ने संभावित जंग छिड़ने की आशंका के मददेनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों खेमों के शूटर फेसबुक व इंस्टाग्राम के अलावा वाट्स एप पर धमकी भरे मैसेज भेजकर खुलेआम हत्या-दूरे को जंग के लिए ललकार रहे हैं। पुलिस को हथ लगे कुछ धमकी भरे मैसेज के बाद पुलिस आयुक्त ने पूरे पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। संश्लस सेल व फ्राइम ब्रांच को खसतौर पर अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जेल से बाहर रहने वाले गैंगस्टरों के शूटरों की पहचान कर उन्हें जल्द दबोचकर हवालात में डाल दिया जाए।

फेसबुक पर जंग का एलान करने से ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कें जल्द खून से लाल हो सकती हैं। गोगी, लारेंस बिस्नोई व काला जठेड़ी खेमे से जुड़े बदमाशों के हाथ लगे कुछ मैसेज से पूरा पुलिस महकमा सकते में है। मैसेज में कहा गया है ..हम अभी चुप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं की हम मर गए, जल्द धमका होगा।। मैसेज में आगे लिखा हुआ है मिस यू गोगी भाई, सलाम सहीदना, जय बलकारी.। नई जंग की शुरुआत है जो हमारे साथ नहीं है। अब से अपना सभी ध्यान रचना। अब इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं। कोई जायज हो या नहीं. आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं, नए नियम का पालन करते हुए जो भी मिला जहां भी.।

फेसबुक पर गोगी के शव की कई तस्वीरें भी अपलोड कर विरोधी गिरोह टिष्ठू को धमकी दी जा रही है। गोगी भाई नाम से बने फेसबुक पर दूसरे मैसेज में कहा गया है कि ऐलान कर दे ऐ मंजिल तेरे शहर में। कदम हमारे कुष्ठ नया करने वाले हैं। बदला

एनसीआर की एकीकृत कार्ययोजना के बिना दिल्ली में वायु प्रदूषण थमना मुश्किल

नई दिल्ली । जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली की भौगोलिक बनावट को भी अनदेखा नहीं कर सकते। 300 किमी के दायरे में दिल्ली की स्थिति ढलान वाली है। इसीलिए उत्तर भारत के इलाकों में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, एयर शेड की वजह से उन सबका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली पर ही पड़ता है। हालांकि दिल्ली के वायु प्रदूषण में दिल्ली की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का कारण बाहर से आने वाला का प्रदूषण होता है। अब देखिए, पिछले करीब एक पखवाड़े से हम नियमित रूप से दिल्ली के पीएम 2.5 और पीएम 10 पर नजर रख रहे हैं। यह लगातार

संतोषजनक श्रेणी में चल रहा है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पाराली जलने की घटनाएं शुरू होंगी, यह श्रेणी खराब या बहुत खराब होने लगेगी। कदने का मतलब, बाहर का प्रदूषण दिल्ली की हवा बिगाड़ देता है। पाराली तो केवल एक कारण है, दिल्ली-एनसीआर की कोई एकीकृत कार्ययोजना नहीं होने से और भी कई मुद्दे प्रदूषण की समस्या को गंभीर बना रहे हैं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर चलता है, लेकिन एनसीआर में अभी तक भी डीजल वाहनों पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में बाहर से आने वाला सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर डीजल पर रहेगा तो

प्रदूषण थामने की दिल्ली की तमाम कोशिशें प्रभावित होंगी ही होंगी। इसलिए एनसीआर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में हमने प्रदूषित ईंधन से चलने वाली सभी औद्योगिक इकायों को 100 फीसद तक पीएनजी में बदल दिया गया है। अन्य राज्यों को भी प्रदूषित ईंधन पर चलने वाली औद्योगिक इकायों को पीएनजी में बदलने का लक्ष्य तो दिया गया है, लेकिन पुख्ता निगरानी के अभाव में पीएनजी पर शिफ्ट करने का काम काफी ढीला चल रहा है।

दिल्ली में कोयले से दो थर्मल पावर प्लांट चलते थे, प्रदूषण की रोकथाम

के मददेनजर दोनों की ही बंद कर दिया गया है। जबकि पड़ोसी राज्यों में न तो उन्हें बंद किया जा रहा है और न ही उन्हें प्रदूषण कम करने वाली नई तकनीक पर लाया जा रहा है। वे हर साल छूट लेते हैं और आज बंद जाते हैं। उन पर जुर्माना लगाया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं।

जुर्माना लगाया इसका समाधान नहीं है। इन्हें या तो नई तकनीक पर लाया जाए या फिर पूर्णतया बंद किया जाए। इनकी जहरीली गैस पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। कम्बोवेश यही स्थिति ईंट-भट्टों की भी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत ही कम पड़ोसी जगजैग तकनीक पर आए हैं। अगर

इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जाड़ों के मौसम में उनका प्रदूषण भी दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को झेलना पड़ेगा।

इसी प्रकार डीजल जेनसेट भी बंद होने चाहिए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने के कारण जेनसेट की उपयोगिता अधिक नहीं है, लेकिन एनसीआर में ये आज भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहतर नहीं होने से जनता को जेनसेट का प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है।

इन पर रोक लगनी अत्यावश्यक है। हमने दिल्ली में पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में पटाखे बेचने और जलाने की

छूट दी जाती है तो प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली के लोग वहां से पटाखे खरीदेंगे। इसलिए सभी राज्यों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी अधिसूचित कर दी है और ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीद पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। जबकि एनसीआर के अन्य राज्यों में इसे लेकर भी ढुलमुल सा रवैया है। पड़ोसी राज्यों को भी इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी को लेकर गंभीर रूख अपनाना चाहिए। मेरे कदने का सीधा सा अभिप्राय यही है कि वायु प्रदूषण से जंग में दिल्ली एनसीआर की एकीकृत कार्ययोजना बननी चाहिए।

संपादकीय

‘ये धुआं-सा कहां से उठता है’

दिल्ली के प्रसिद्ध कवि मीर ने एक बार पूछा था, देख तो दिल कि जां से उठता है, ये धुआं-सा कहां से उठता है। गजल का यह मतला कोई ढाई-सी साल पुराना है। दिल्ली में हम आज भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, चाहे मीर का अंदाज-ए-बयां न भी हो। एक नया आकलन बताता है कि दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने वालों की उम्र उम्मीद से करीब दस साल कम रह जाती है। उत्तर भारत के लिए यह आंकड़ा साढ़े-आठ साल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले अपनी अपेक्षित आयु से सात-आठ साल पहले ही वायु प्रदूषण की बलि चढ़ जाते हैं। इस तरह के तथ्य ढाई दशक से लगातार सामने आ रहे हैं। किंतु सेहत को नुकसान भी बढ़ रहा है और जान को जोखिम भी। झोली भर-भरकर ओलंपिक पदक बटोरने की आकांक्षा करने वाली दिल्ली के हर तीसरे बच्चे का फेफड़ा इस समय कमजोर पाया जा रहा है। वायु प्रदूषण की हमारी समझ जितनी गहरी होती जा रही है, इससे निपटने का हमारा बूता उतना ही घटता दिख रहा है। कभी-कभी साहित्य में ऐसी बात सहज ही दिख जाती है, जिसे समझना विज्ञान के लिए कठिन होता है। उत्तर भारत के पुराने किस्से-कहानियों में गांवों पर खड़े हुए धुएं का वर्णन मिलता है। उस समय न तो कोयला जलाने वाले कारखाने थे, न ही डीजल-पेट्रोल की गाड़ियां ही। वह कुछ आंश में जलते चूल्हों का था। रसोई गैस का चलन आने के बाद लकड़ी और कंड़े का इस्तेमाल कम हुआ है, किंतु दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर भारत में ही है। ऐसा नहीं है कि बाकी भारत में धुआं उगलने वाले उद्योग या ट्रैफिक नहीं है, किंतु उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का भूगोल बाकी देश से अलग है। इसे ध्यान में रखें, तो वायु प्रदूषण की मार समझ में आती ही है, गंगा-यमुना जैसी नदियों के प्रदूषण के कारण भी साफ होते हैं। हम जिस भूखंड पर रहते हैं, वह लाखों साल पहले एशिया से टकराया था। हिमालय इसी टकरा से पैदा हुआ, इसी से हमारा उत्तरी भूभाग एशिया के नीचे दब रहा है, जबकि तिब्बत समुद्र से साढ़े-तीन किलोमीटर ऊपर पहुंच गया है। इस निचले इलाके के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में छोटानागपुर और मालवा के पठार भी हैं और विस्थापित पर्वत माला भी।

यह खाई हमें दिखती नहीं है। इसे हिमालय से आने वाली प्रचंड नदियों ने उसकी मिट्टी से, उसके गाद से भर दिया है। तभी पंजाब से बंगाल तक ऐसा सपाट मैदानी इलाका है, जो पानी ही बना सकता है। इस निचले इलाके के उत्तर-दक्षिण, दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसके पश्चिम की ओर थार का मरुस्थल है, जहाँ से रेत के कण उड़ के आते हैं। यानी यह एक भीमकाय घाटी है। यमुनोत्री और गंगोत्री से निकलने वाली धाराएँ बंगाल जाकर समुद्र से मिलती हैं। इनके करीब आने से ही उत्तरने वाली सतलुज जैसी नदियाँ सिंधु में मिलकर अरब सागर में विसर्जित होती हैं।

पंजाब से बंगाल तक के इस निचले इलाके में बाकी देश की तुलना में हवा कम चलती है। हिमालय के ऊंचे शिखरों से निकली बर्फीली हवाओं से इस इलाके के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से पर एक ठंडी चादर जैसी बिल्ली रहती है। यानी यहाँ का धुआं उतनी आसानी से उठकर छितराता नहीं है, जितना दक्षिणी या पश्चिमी भारत में होता है। यानी दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना जैसे नगर ऐसे क्षेत्र में बसे हैं, जिसकी हवा किसी 'प्रेशर कुकर' की तरह बंद है। आज की राजनीति पर्यावरण की बलि चढ़ाना चाहती है। उसका दावा है कि एक बार खुशहाल हो गए, तो उसके बाद पर्यावरण भी सुधार लेंगे। लेकिन यह कोरा झूठ है। हमारी रोजी-रोटी राजनीति और विकास से नहीं, कुदरत की नेमत से है। पर्यावरण का नाश करके हम विकास का ब्याज नहीं कमा सकते हैं। राजनीति का आयकर चुकाना तो बहुत दूर की बात है। इस पूरे क्षेत्र में धुआं पैदा करने वाले सभी उद्यमों की सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन यह काम बहुत कठिन है। हमारी लामाण आभी आबादी इस इलाके में बसती है। इसके कारण भी भूगोल में मिलता है। कृषि पैदावार नदियों के किनारे अधिक होती है। हिमालय की मिट्टी उर्वर है। नदी किनारे कई और बुध्दियाएँ मिलती हैं। सड़क और रेल के विस्तार से पहले यातायात का कुछ साधन नदियाँ ही थीं। आधुनिक विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति नदियों के किनारे नहीं मानता है, पर सभ्यता तो नदी किनारे ही पानी पी। बड़े राज्य नदियों के किनारों से ही खड़े हुए हैं, साम्राज्य भी। इससे समझा जा सकता है कि गंगा इतनी प्रदूषित क्यों है, यह भी कि उसे साफ करना इतना कठिन क्यों है, जबकि इसके लिए कार्यक्रम 1986 से चल रहे हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत का पानी भी गंगा में आकर मिलता है। इतने बड़े इलाके का मैला पानी ही नहीं, सभी जहरीले पदार्थ इस्तेमाल होने के बाद गंगा में पहुँचते हैं। हम जो दवाएँ खाते हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा हमारे मल-मूत्र से निकल जाता है। यह दूसरी नदियों से भरा हुआ गंगा में धुँआं पड़ता है। जब करोड़ों लोगों का अपशिष्ट नदियों में मिले, तब कोई अस्वच्छ नहीं कि गंगा के इलाके में कैंसर रोग अत्यधिक है। हमारी राजनीति का भूगोल से कोई लेना-देना नहीं है। हम धर्म या जाति या क्षेत्र के आधार पर अपना-परया तय करते हैं। किसी पहचान को रूढ़ मानकर अपने को दूसरे से अलग करना सुविधाजनक होता है। राजनीति को इससे लाभ होता है। जब कभी राजनीति इससे उबरने की कोशिश करती है, तब उसे 'विकास' दिखता है। विकास का मतलब है कोयला और पेट्रोलियम जलाकर वायु प्रदूषण करना, नदियों का पानी निचोड़कर उनमें मैला डालना। इसके अलावा जो भी विकास की बात होती है, वह निराधार है। इसी विकास के अंतर्गत दिल्ली में 20 करोड़ रुपये की कीमत पर एक धुआं कम करने का 'स्मॉग टावर' लगा है। विकास की राजनीति से निकले उपचार तो उसके रोग से भी ज्यादा बीभत्स हैं। मीर से माफ़ी मांगते हुए कह सकते हैं, 'उट्टरी हो गई सब तदबीरें' कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी-ए- 'विकास' ने आखिर काम तमाम किया। अगर हम अपने समाज को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हमें विकास की सीमा तय करनी होगी। आज की राजनीति पर्यावरण की बलि चढ़ाना चाहती है। उसका दावा है कि एक बार खुशहाल हो गए, तो उसके बाद पर्यावरण भी सुधार लेंगे। लेकिन यह कोरा झूठ है। हमारी रोजी-रोटी राजनीति और विकास से नहीं, कुदरत की नेमत से है। पर्यावरण का नाश करके हम विकास का ब्याज नहीं कमा सकते हैं। राजनीति का आयकर चुकाना तो बहुत दूर की बात है!

प्रवीण कुमार सिंह

इतिहास लेखन को देनी होगी नई दृष्टि, नहीं तो इतिहास के कई गौरवपूर्ण तथ्य बने रहेंगे अनजान

अधिकांश इतिहासकारों

ने संस्कृतীয় आख्यान को

स्वीकार किया और भारत

विद्या को यूरोपीय खांचे से

बाहर निकालने का

महत्वपूर्ण कार्य भी किया।

राष्ट्रवादी इतिहासकारों को

प्राथमिकता के आधार पर

उकट बलिदान की उन

घटनाओं और तथ्यों को

खोजना होगा, जो इतिहास

में दफन हो गई हैं। उन

घटनाओं को पाठ्य

पुस्तकों में अनिवार्यत-

शामिल भी किया जाना

चाहिए। साथ ही उन

ऐतिहासिक तथ्यों और

घटनाओं को कारण और

परिणाम की सुव्यवस्थित

श्रृंखला में रखकर

विवेचित किया जाना

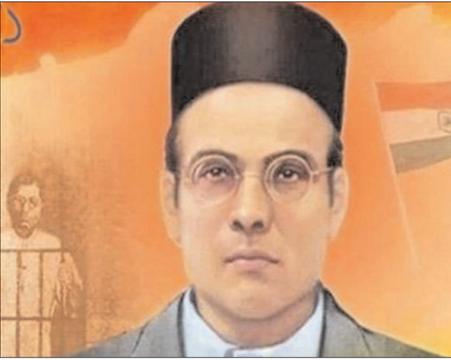
चाहिए। जब तक यह कार्य

नहीं होता तब तक इतिहास

के कई गौरवपूर्ण तथ्य

अनजान बने रहेंगे।

खिलाफ 1922 में हुए मोपला नरसंहार का पर्याप्त विवरण भी



इतिहास की पुस्तकों में जलियावाला बाग और चौरीचौरा जैसी घटनाओं का वृत्तांत तो मिलता है, किंतु स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसी कई खोफनाक घटनाएँ घटीं, जो आज भी इतिहास में दफन हैं। जैसे अदीलाबाद का गोंड नरसंहार। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने जब तेलंगाना के गोंड राज पर नियंत्रण करना चाहा तो रजाकारों के खिलाफ फौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध करने वाले रामजी गोंड ने क्षेत्र के गोंड आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी सेना के साथ सशस्त्र संग्राम किया और अंग्रेजों को पराजित किया। हालाँकि, बाद में अंग्रेजी फौज ने हथियारों के बल पर गोंड क्षेत्र में प्रवेश किया और लूट-पाट की। अंग्रेजों को सूचना मिली कि रामजी गोंड अदीलाबाद के निर्मल गांव में हैं तो अंग्रेजों ने उन पर धावा बोल दिया। रामजी गोंड अपने एक हजार आदिवासी सहयोगियों के साथ पकड़े गए। उन सबकों नौ अप्रैल, 1860 को एक वट वृक्ष की डाली पर फांसी दे दी गई।

यह दुयोंग ही है कि उसके ठीक तीन साल पहले उसी तरह बंगाल के बैरकपुर में एक वट वृक्ष की डाली पर आठ अप्रैल, 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। वह बूढ़ा वट वृक्ष आज भी गौरवशाली इतिहास और स्मृतियों को अंक में दबाए निशब्द खड़ा है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855-56 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा (ओडिशा) के संथालों ने संग्राम किया था। न उन संथालों के संग्राम के बारे में और न ही अदीलाबाद के गोंड नरसंहार के बारे में इतिहास की पुस्तकों में विवरण मिलता है। इसी तरह केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के भूमि कानून के

क दिया था। अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों में भेदभाव के

उनका एक ध्येय था। इतिहास लेखन को सांख्यिक रूप देने के लिए विलियम जोस के प्रयासों से 1884 में एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल की स्थापना हुई। हालाँकि, पश्चिमी प्राच्यवाद के आधार पर लिखे गए भारत के इतिहास को आरसी दत्त, एचसी राय चौधरी, काशीप्रसाद जायसवाल, बेनी प्रसाद, आरसी मजूमदार और आरके मुखर्जी जैसे भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने चुनौती दी और इतिहास लेखन को एक राष्ट्रवादी दृष्टि प्रदान की।

राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पश्चिमी प्राच्यवाद के आख्यानों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य धारणाओं को भी खारिज किया। जो इतिहासकार भारत के 1857 के संग्राम को सिपाही विद्रोह मान रहे थे, उन्को मत को विनाशक दामोदर सावरकर की पुस्तक 'वार आफ इंडिपेंडेंस 1857' ने खारिज किया। दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट सोवियत संघ की भी सावरकर के मत को स्वीकार किया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने 1857 के संग्राम से संबंधित मार्क्स और

हाथी साइकिल और बुलडोजर.. लॉन्ग हुआ यूपी का चुनावी टीजर!

उत्तर प्रदेश में सत्ता का ऊंटज हाथीज बुलडोजर का साइकिल पर सवार समाजवादी किस तरफ बेटेगा ये तो आने वाला वक्त ही जानता है। लेकिन चुनावी दहलीज पर पहुंचने से पहले ही यूपी में वाक्यवृद्ध शुरू हो चुका है। अब मायावती हों या ओवैसी या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर कोई वार-पलटवार में व्यस्त है। लेकिन इस चुनावी वार में जो शख्स सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव . बिना अच्छे-बुरे में भेदभाव किए अखिलेश यादव का रिंगल पॉइंट एजेंड है, सीएम योगी के हर काम पर तंज करसना. यूपी में जबसे योगी सरकार ने कामना सभाली है तभी से ही अपराधियों के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है. अब वो कोई पेशेवर गैंगस्टर हों या फिर शराब का तस्कर, हर किसी की अवैध संपत्ति पर सीएम योगी का बुलडोजर पिछले दिनों जमकर चला है और अभी भी चल रहा है. सीएम योगी के अवैध संपत्ति सफाई अभियान के तहत योगी प्रशासन करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को अपने शिक्के में ले चुका है. ये संपत्ति अवैध शराब का व्यापार करने वाले और दूसरे अवैध कामों में लिप्त अपराधियों से जुड़ी है. अब क्योंकि संपत्ति गैर-कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी और योगी सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए. लेकिन सीएम योगी के इस सराहनीय काम से भी यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को समस्या हो गई. और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को सलाह दे डाली कि वो अपनी पार्टी का सिंबल बुलडोजर को ही बना लें. अखिलेश ने कहा, योगी सरकार गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है. इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर ही रख लेना चाहिए. अवैध संपत्ति अखिलेश यादव ने सीधे

सीएम योगी पर हमला बोला था तो योगी भी कहा चुप रहने वाले थे.

सीएम योगी ने अपने सधे हुए अंदाज में अखिलेश को जबब दते हुए ट्वीट किया और लिखा, निर्दोष लोगों की संपत्ति व सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही उपाचार है - बुलडोजर. बसपा प्रमुख

मायावती से ज्यादा एक्टिव यूपी में आजकल .दृष्ट्करू प्रमुख असदुद्दीन

ओवैसी नजर आ रहे हैं. जहां चुनाव होता है वहीं ओवैसी पहुंचे जाते हैं.

वार-पलटवार करते हैं. मांटी से लेकर योगी तक को घेरते हैं. ओवैसी के चुनावी अभियान यूपी में चला तो राजनीति में एंट्री 'अब्बाजान' और

'चंचाजान' की भी हो गई. दरअसल एक रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी के लोगों का राशन

पहले अब्बाजान हड़प जाते थे. अब अब्बाजान पर राजनीति हुई तो मैदान

में ओवैसी भी कूद पड़े और ओवैसी ना कहा, जिस-जिस मजलूम पर जुल्म होगा, मैं उस मजलूम का अब्बा

जान हूं. यूपी के चुनावी समर में ओवैसी की सीटों का भले ही कुछ

अता-पता ना हो, लेकिन ओवैसी की चुनावी चौकड़ी धर्म के नाम पर वोटों का धुंधीकरण करने में जबदस्त

तरीके से जुटी है. जिसका नतीजा 4-6

महीने बाद हम इसी के सामने होगा. सोशल मीडिया का इस्तेमाल

कर अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए साहकिल लेकर

निकल चुके हैं. नाह है 'बाइस में बाइसिकल', लेकिन मायावती का

हाथी लगाता है यूपी की गलियों में कहीं

बाह्रणों के पास जाता है तो कभी कहीं और, उसकों कोई एक छोर

मिलता नजर नहीं आ रहा है. लाइक

कमेंट और रीटवीट के राजनीतिक दौर में भी मायावती बहुत पीछे रह गईं

हैं. तो दूसरी तरफ सीएम योगी का बुलडोजर ही रख लेना चाहिए.

'ध्वंसीकरण' की नीति पर आगे बढ़ रहा है.

किसानों को लुभाने की कोशिश में राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन गई है एमएसपी

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की चर्चा वे लोग भी करते हैं, जिन्होंने न खेत देखा, न खेती और न ही खेतिहरों की हालत। किसान भी सिर्फ उन्हें कहा जा रहा है, जिनके नाम जमीन हैं। वे खेती करें या न करें। बात सिर्फ एमएसपी की हो रही है, वह भी खरीद की गारंटी के साथ। भविष्य की एमएसपी कैसी हो? इस चर्चा से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह आई कहां से और किसके लिए थी। कोई 55 साल पहले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गठन के साथ एमएसपी की शुरुआत हुई थी, जो आज भी जारी है।

देश की भूखमरी खत्म करने के लिए एमएसपी का उपयोग किसानों से गेहूँ खरी चिावल लेवी के तौर पर किया जाता था। खुले बाजार में अनाज का मूल्य अधिक था और लेवी वाला मूल्य यानी एमएसपी कम होती थी। किसान इस मूल्य पर अनाज देने को राजी नहीं होते थे, लेकिन गेहूँ की खेती के रकबा के हिसाब से किसानों को गेहूँ देना पड़ता था। सार्वजनिक राशन प्रणाली (पीडीएस) के तहत गाँवों को रियायती दर पर अनाज बांटने की कुछ जिम्मेदारी किसानों को भी उठानी पड़ती थी। उसी दौरान हरित क्रांति की लौ से कृषि जगत जगमगाया। चोतरफा किसानों ने अन्य सभी फसलों की खेती छोड़ गेहूँ एवं धान की खेती करनी शुरू कर दी। बदलती परिस्थितियों के बीच बाजार में इन दोनों अनाजों की बहुतायत का नतीजा यह हुआ कि इनकी कीमतें घटने लगीं। खुले बाजार के मुकामले एमएसपी अधिक हो गई। किसान सरकारी खरीद केंद्रों की ओर मुड़ने लगे। राज्यों के बीच भी सरकारी खरीद बढ़ाने की होड़ लग गई। गेहूँ-चावल के साथ खेती एकांगी होती गई और बाकी फसलें गौड़। खेती-बाड़ी से बाड़ी बाहर हो गई। एमएसपी राजनीतिक दलों के

हाथों का खिलौना बन गई। चुनावों के पहले एमएसपी के रास्ते किसानों को लुभाने की कोशिश होती रही है। देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के संतुलित प्रबंधन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा गोदामों के साथ सबका पेट भरने के बावजूद भारत दुनिया के 107 देशों के हॉरंड इटेक्स में 94वें स्थान पर है। आजादी के 75वें साल में हम पोषण अभियान चलाने के लिए फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन वाले अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया। जिस एमएसपी के रास्ते गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया, उसका उपयोग गैर अनाज वाली फसलों पर नहीं किया गया।

एमएसपी लाने वाली एलके झा कमेटी की सिफारिशों पर पूरी तरह कभी गौर नहीं किया गया। उनकी रिपोर्ट में ही कहा गया है, 'डेफिसिट फ्यूडोन इकोनोमी के लिए एमएसपी वरदान साबित होगा, जबकि सरप्लस फ्यूडोन इकोनोमी में यह अधिभार हो सकता है।' आज देश में खाद्यान्न का भारी उत्पादन हो रहा है। गोदाम भरे पड़े हैं। निर्धारित बफर और पीडीएस के लिए आवश्यक स्टॉक के मुकामले बहुत अधिक अनाज है। देश की 80 करोड़ से अधिक आबादी को मुफ्त में अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरत मांग आधारित खेती की है। अनाज की जगह अन्य तिहनी और दलहन की फसलों की खेती पर जोर देने की जरूरत है। इसी तरह की फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में वैसे तो 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा गन्ना, गेहूँ एवं धान के किसानों को हो रहा है। इसके अलावा बागवानी, डेयरी, पशुधन, मत्स्य एवं पोल्ट्री किसानों को इसका

लाभ कभी नहीं मिला। जबकि इनमें लगे किसान छोटे अथवा मझोले किस्म के हैं। बिना किसी सरकारी समर्थन यानी न एमएसपी और न ही कृषि क्षेत्र के संतुलित प्रबंधन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा गोदामों के साथ सबका पेट भरने के लिए न बाजार की कमी है और न ही सरकारी समर्थन की जरूरत। उन्होंने बाजार की मांग को समझा और उसी के अनुकूल अनाज निकाला। लिहाजा वे फायदे में रहे। जिन किसानों को मुफ्त निर्धारण जैसी सरकारी मदद प्राप्त होती रही वे आज भी सरकार के भरोसे खेती करते हैं। अब तो एमएसपी के कानूनी हक और खरीद की गारंटी जैसी मांग को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।

अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगलुरु में 'एमएसपी इन प्यूचर' विषय पर कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्धारकों, किसान प्रतिनिधियों और जिस सरकार के जानकारों के साथ विमर्श किया गया। इस दौरान सभी ने एमएसपी के मौजूदा स्वरूप को नकारते हुए कई तरह के विकल्प सुझाए। इसमें सबसे माना कि किसानों की आर्थिक मदद होनी चाहिए, वह पीएम-किसान योजना से नगदी की मदद हो अथवा अन्य कोई। धान एवं गेहूँ की जगह फसल विविधीकरण पर अगर जोर दिया जाए तो उन वैकल्पिक फसलों की उचित कीमत पर खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों को परंपरागत फसलों से हटाने और दूसरी फसलों की खेती का विकल्प तभी सफल होगा जब उन्हें फायदा दिखेगा। कृषि उपज से बायोफ्यूल तैयार करने की सरकार की ताजा मुहिम तभी रंग लाएगी जब किसानों को उससे संबद्ध उद्योगों पर विश्वास जमाए।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिले बढ़ावा, बेलगाम बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने में होंगे मददगार

फिर भी हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण का सिर्फ स्थान परिवर्तित होता है। यह बिजली खपत वाले इलाकों से बिजली उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होता है। यदि 100 पेट्रोल कारों के स्थान पर 500 इलेक्ट्रिक कारें चलने लगीं तो प्रदूषण कम नहीं होगा। सिर्फ उसका स्थान बदल जाएगा. प्रदूषण को कम करने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर बोझ कम करना होगा। इसलिए सरकार को सार्वजनिक यातायात सुविधाओं में भी तेजी से सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार तमाम शहरों में मेट्रो रेल चलाई जा रही है, उसी के समानांतर छोटे शहरों में बस की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, तो लोगों की व्यक्तिगत कार में यात्रा करने की जरूरत कम हो जाएगी।

नावों ने एक अहम फैसला किया है कि वर्ष 2025 के बाद वहां केवल और केवल इलेक्ट्रिक कारों ही चलेंगीं। डेनमार्क और नीदरलैंड ने इसकी मिसाल 2030 तक की है। इंग्लैंड ने इसके लिए 2035 की समय सीमा निर्धारित की है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया भी बिल्कुल इंग्लैंड के नवशेकदम पर है। इन संकेतों से स्पष्ट है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण कम होता है। हालाँकि, इसका एक दूसरा पहलू भी है। वह यह कि अमूमन शहरों में तो बिजली बनती नहीं, लेकिन जिन इलाकों में बिजली का उत्पादन होता है वहां के पर्यावरण पर जरूर इसका कुछ असर पड़ेगा। फिर भी इलेक्ट्रिक कार शहरों में बेलगाम बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने में मददगार होंगीं। चूंकि कामकाजी आबादी का एक बड़ा वर्ग शहरों में ही रहता है तो पर्यावरण को मिलने वाले फायदे से समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ मिलना बहुत स्वाभाविक है। इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों से एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं। खासतौर से भारत जैसे देश के लिए तो ये और भी उपयोगी होंगीं, जो पेट्रो उत्पादों के लिए एक बड़ी हद तक आयात पर ही निर्भर है। किसी भी उत्पाद की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता में उसकी कीमत एक अहम कारक होती है। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में सुकरन की बात सही है कि उसमें लगने वाली बैटरी के दाम घटने पर है। यही बैटरी इलेक्ट्रिक कार की लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। बैटरी के दाम घटने का असर इलेक्ट्रिक कार की कीमत पर भी दिख रहा है। विश्व अर्थिक मंच के एक अध्ययन के



अनुसार, 2019 में पेट्रोल की कार का दाम 24 हजार डालर था जो 2021 में 25 हजार डालर हुआ और 2025 में उसके 26 हजार डालर होने का अनुमान है। इसके उलट इलेक्ट्रिक कार के दाम में कमी आई है। 2019 में इलेक्ट्रिक कार का मूल्य 50 हजार डालर था जो 2021 में 39 हजार डालर रह गया और 2025 में पेट्रोल कार से भी सस्ता 18 हजार डालर होने का अनुमान है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि चीन में इस वर्ष की पहली तिमाही में पांच लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं और यूरोप में साढ़े चार लाख कारों की बिक्री हो चुकी है। वहीं भारत में केवल 60,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकने का अनुमान है। इस दौड़ में हम पीछे

हैं वह भी तब जब इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी सब्सिडी से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कुछ तेजी अवश्य आई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बेहतर होगा कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने के बजाय पेट्रोल वाहनों पर टैक्स लगाने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए। तभी देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में आशातित बढ़ोतरी संभव हो सकेगी।

बोते दिनों आस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन के अनुसार, कई अर्थशास्त्रियों ने इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने का समर्थन किया। उनमें से 10 प्रतिशत ने सब्सिडी की जगह पेट्रोल वाहनों पर

कार्बन टैक्स की वकालत की। इन दोनों तरीकों से पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाती है। अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने से सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल कार पर कार्बन टैक्स लगाने से सरकार को राजस्व मिलेगा। प्रश्न है कि जो कार्य आय अर्जित करते हुए संभव है उसी कार्य को खर्च करके क्यों किया जाए? इसलिए पेट्रोल कार पर टैक्स लगाया उचित लगता है।

कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि पेट्रोल कार पर टैक्स लगने से कार के दाम बढ़ेंगे, जिसका उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल, जब सरकार सब्सिडी देती है तो उसके लिए जनता से किसी न किसी रूप में कोई टैक्स वसूल करती ही है। प्रश्न यह है कि पेट्रोल पर टैक्स लगाकर जनता पर भार डाला जाए अथवा इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देकर उसी जनता पर भार डाला जाए। फर्क यही है कि जब हम पेट्रोल कार पर टैक्स लगाएंगे तो उस विशेष उपभोक्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा जो पेट्रोल कार खरीदता है। इसकी तुलना में जब हम इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देते हैं, तो आम जनता पर टैक्स का भार पड़ता है। इसलिए यही उचित प्रतीत होता है कि सरकार पेट्रोल कार पर टैक्स लगाए जिससे कि अधिक प्रदूषण फैलाने वालों पर सीधा भार पड़े और आम आदमी इसके बोझ से बचा रहे।

इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए एक और नीति में परिवर्तन जरूरी है। तमाम देशों में समय के अनुसार यानी सुबह, दोपहर और शाम को बिजली की अलग-अलग दरें निर्धारित होती हैं। जैसे मध्य रात्रि में बिजली का दाम दो रुपये प्रति

यूनिट हो सकता है तो दिन में बढ़ी हुई मांग के दौरान आठ रुपये प्रति यूनिट। वहीं, किसी देश में दिन के दौरान सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही हो, तो उसकी दर दो रुपये यूनिट हो सकती है, जबकि रात में उत्पादन की लागत बढ़ने पर आठ रुपये तक। इसलिए आवश्यक है कि अपने देश में समयानुसार बिजली का मूल्य निर्धारित किया जाए। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक कार वाले अपनी सुविधा के हिसाब से कार को चार्ज कर सकेंगे। इससे इलेक्ट्रिक कार और किफायती हो जाएंगीं। वहीं बिजली की खपत का परिदृश्य भी सुधरेगा। स्पष्ट है कि सरकार अगर इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ाना चाहती है, तो उसे दो नीतिगत परिवर्तन करने होंगे। पहला यही कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने के स्थान पर पेट्रोल कार पर टैक्स लगाए। दूसरा यह कि समय के अनुसार, बिजली की दरों को निर्धारित करें। फिर भी हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण का सिर्फ स्थान परिवर्तित होता है। यह बिजली खपत वाले इलाकों से बिजली उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होता है। यदि 100 पेट्रोल कारों के स्थान पर 500 इलेक्ट्रिक कारें चलने लगीं तो प्रदूषण कम नहीं होगा। सिर्फ उसका स्थान बदल जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर बोझ कम करना होगा। इसलिए सरकार को सार्वजनिक यातायात सुविधाओं में भी तेजी से सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार तमाम शहरों में मेट्रो रेल चलाई जा रही है, उसी के समानांतर छोटे शहरों में बस की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, तो लोगों की व्यक्तिगत कार में यात्रा करने की जरूरत कम हो जाएगी।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91

से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फ़ैक्स नं. 011.22786172

RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

श्रमिकों को भी मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही योगी सरकार, पांच लाख रुपये तक करा सकेगे इलाज

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्दी मंजूर कराने की तैयारी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना से छूटे गरीबों-बंचितों को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क कैशलेस इलाज कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुद्देंया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का एलान किया था।

चातुर्वितीय वर्ष के बजट में इस योजना लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक रजिंकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी कंप्नीहेसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से कराएगा। इसके लिए बोर्ड और साचीज के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए यह योजना बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2021 शुरू की है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश निवासियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आरोग्य भारत मुहीम के तहत अस्पतालों में होने वाले खर्च के बिना ही अपना इलाज करवाने की सुविधा दी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने वलस्टर विकास की राशि के खर्च पर जताई नाराजगी

रांची। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एमएन सिन्हा ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों को रूबन मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने वलस्टर विकास की राशि के खर्च पर असंतोष जताया है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिला किसानों को जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने रूबन मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक के दौरान रूबन मिशन के संचालन से जुड़े 15 जिलों के उप विकास आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। मनरंगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बैठक के दौरान रूबन मिशन की प्रगति पर आधारित प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उन्होंने साहिबगंज के 12 एवं पाकुड़ के दो पलाश मार्ट का आनलाइन उद्घाटन किया। केंद्रीय सचिव एमएन सिन्हा ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाकर जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने अनुमोदित डीपीआर के एवज में खर्च कम होने पर कहा कि पूर्व से अनुमोदित परियोजनाओं में अगर बदलाव की जरूरत है तो उसे नियमानुसार करना चाहिए। रूबन मिशन के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव ने सभी स्ट्रेकहेल्ड्स एवं प्रखंड विकास पर्याकारियों के साथ कार्यशाला करने की सलाह दी, ताकि समन्वय बेहतर हो सके और वलस्टर विकास का काम जल्द पूरा हो सके। उन्होंने सखी मंडलों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए ग्राम संगठन का गठन में तेजी लाने को कहा। समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास सचिव डा. मनीष रंजन, मनरंगा कमिश्नर राजेश्वरी बी, सीईओ जेएसएलपीएस नैन्सी सहाय समेत रूबन मिशन, जेएसएलपीएस एवं मनरंगा के अधिकारी उपस्थित थे। मंडल को पोषण वाटिका पहल से जोड़ें- केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने सखी मंडल की महिलाओं को सशक्त आजीविका से जोड़ने के प्रयासों पर फोकस करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों के आजीविका आधारित कार्यों का जट्टा संहार करें। सखी मंडल को पोषण वाटिका पहल को शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने पशुपालन में आने वाली दिक्कतों को दूर कर सुदूर गांव के परिवार तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम करने को कहा।

दो दिनों से गायब सगी बहनों का शव गांव के बगल में स्थित तालाब से मिली ; पुलिस जुटी जांच में

गिरिडीह । सरिया के केसवारी से मंगलवार की शाम लापता दो सगी मामसू बहनों का शव गांव के बगल में ही स्थित तालाब से बुधवार को मिला। मृतकों में तीन बचपन शाहीन परवीन एवं दो वर्षीय नाजिया परवीन शामिल हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरिया थाना पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी प्रेम कुमार इंस्पेक्टर व दिनेश सिंह घटना स्थल पहुंचे। पुलिस दोनों शवों को म अपने कब्जे में लेकर सरिया थाना ले आई। घटना को लेकर मृतक बच्चियों के दादा सब्जर अंसारी ने बताया कि मंगलवार की सुबह लगभग आठ बजे अपने दोनों पोतियों को कुछ खाने का समान देकर कुछ काम से वह घर से बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद घर वापस आकर उनकी खोजबीन की लेकिन, उसका कुछ अंता पता नहीं चला। इसके बाद दिन भर स्टेशन, हट बाजार, आस पड़ोस में जानकारी ली। बाद में देर शाम को सरिया थाना में बच्ची के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। वही बुधवार की सुबह दोनों बच्चियों के शव तालाब के किनारे पानी में देखा गया। इसकी सूचना सरिया थाना पुलिस को दी गई। इधर स्वजनों ने बताया कि जिस तालाब में दोनों बच्चियों का शव मिला उस तालाब में मंगलवार को जाल की मदद से तलाश की गई थी लेकिन, कुछ पैदावद नहीं हुआ था। दिन दान बाद उसी तालाब से शवों का मिलना संदेह बर्दा करता है। इस संबंध में स्वजनों ने किसी पर शक नहीं किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि बच्चियों के गुम होने की शिकायत स्वजनों ने मंगलवार की शाम को की थी। पुलिस खोजबीन में जुटी हुई थी । इसी बीच घर के बगल के बेकार पड़े तालाब से शवों के मिलने की सूचना पर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। स्वजनों ने अभी तक किसी पर शक या आरोप नहीं लगाया है। देखने से तालाब में डूबने से मौत की घटना प्रतीत हो रही है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है।

महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 तक

रायपुर । राज्य शासन द्वारा तीरंदजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन एक नवंबर को महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में उन्हें एक लाख रुपये नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सर्वोच्च खिलाड़ियों से महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान 2021-22 के लिए अनुशंसाएं आमंत्रित की गई है।

अनुशंसाएं जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है।हच्छुक खिलाड़ी अपना आवेदन खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हाकी स्टेडियम, जीई रोड रायपुर या खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों में निर्धारित तिथि में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जिन्होंने वर्ष 2020-21 में तीरंदजी की राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीनियर वर्ग या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या तीरंदजी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। यदि तीरंदजी में उपरोक्त उपलब्धियों वाले खिलाड़ी किसी वर्ष में नहीं मिले तो उस वर्ष अन्य ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के खेल परस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लेता है। महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान के लिए उपरोक्त निर्णयों की विस्तृत जानकारी खेल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लांच किया निर्भया-एक-पहल अभियान, हर जिले में प्रशिक्षण लेंगी एक-एक हजार महिलाएं

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया-एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75000 महिलाओं को उद्यमिता की प्रशिक्षण किट का वितरण हुआ। इस मौके पर सीएम योगी एक जनपद, एक उत्पाद योजना का विशेष झक टिकट और लिफाफ़ा का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर आले तीन माह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंक और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उद्यम शुरू कराकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। इस दौरान सभी 75 जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित

हम आतंकवादी नहीं, गोरखपुर का विकास देखने आए हैं..दोस्तों ने बताया, पुलिस ने कैसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

गोरखपुर। हरियाणा के मेवात, नूह निवासी हरबीर सिंह व गुडगांव के सेक्टर 48 निवासी प्रदीप कुमार का कहना है कि उनका कहना है कि उनके दोस्त व कानपुर के प्राप्रटी डीलर मनीष गुप्ता ने सोमवार की रात रामद्वताल थाना पुलिस से सिर्फ इतना ही कहा था कि आतंकी नहीं हैं हम, गोरखपुर का विकास देखने आए हैं।

उनका कहना है कि मनीष का यह कहना उसके लिए काल बन गया। पुलिस ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दोनों का कहना है कि गोरखपुर को लेकर उन्होंने अपने भीतर क्या-क्या सपने सजोये थे, लेकिन जैसे ही गोरखपुर का नाम सामने आ रहा है तो पुलिस की बर्बरता में यहां अक्स ही जेहन में नहीं

उभर पा रहा है। दोनों बार-बार लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मनीष का पोस्टमार्टम कब पूरा होगा। उन्हें यहां से कब जाने को मिलेगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बस एक बार यहां से जाने का मौका मिल जाए। दुबारा अपने किसी परिचित से गोरखपुर जाने के लिए नहीं कहेंगा।

शहर के तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस के कमरा संख्या 512 में ठहरे हबीर सिंह व प्रदीप कुमार ने बताया कि हबीर व मनीष प्राप्रटी डीलिंग का कारोबार करते हैं। प्रदीप इवेंट मैनेजर का काम करते हैं। उनका कहना है कि तीनों दोस्तों ने काफी कुछ सुन रखा था गोरखपुर के विषय में। यहां विकास के बहुत काम हुए हैं।

मोतिहारी के फेनहारा में पुलिसकर्मों को पीटा, एक हिरासत में, वीडियो वायरल

पूर्वी चंपारण । पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के फेनहारा प्रखंड क्षेत्र की रूपौलिया पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 48 पर बुधवार को फर्जी मतदाताओं को रोकने के दौरान जमकर झड़प हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने एक जमादार की पिटाई कर दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। इस दौरान पुलिस ने श्री नारायण पांडेय नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि यहां पंचायत चुनाव को लेकर वोट खला जा रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर हंगामा हो गया और एक जमादार अत्यय राय की जमकर पिटाई कर दी। यहां बता दें कि मोतिहारी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां तैयारी, फेनहारा और मधुबन प्रखंड में वोटिंग हो रही है।

पूर्वी चंपारण में मतदान केंद्रों पर लगी रही कतार- मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिला

लुधियाना में चोरी के बाइक व मोबाइल समेत दो गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

लुधियाना। चोरी के मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगा कर लूटपाट व झपटमारी की वारदातें करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके बुधवार उन्हें अदालत में पेश किया। जहां से 1 दिन का रिमांड हासिल करने के बाद कड़ी पूछताछ की जा रही है।

एएसआइ सुरिंदर कुमार ने बताया कि आरोपितों की पहचान नूरवाला रोड के बजरंग विहार निवासी संदीप सिंह तथा बहदर के रोड स्थित सब्जी मंडी की जुगियायों में रहने वाले राहुल कुमार के रूप में हुई। मंगलवार शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपित चोरी के मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगा कर लूटपाट व झपटमारी की वारदातें करते हैं।

आज भी दोनों काकोवाल रोड स्थित बिजली दफ्तर के आसपास किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर वहां की गई

मसूरी में भूमिगत होंगी बिजली की लाइनें, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने अफसरों को दिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश

मसूरी। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही मसूरी में विद्युत लाइनों को भूमिगत कर दिया जाएगा। ऊर्जा निगम के अफसरों को इसके लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिफनकोट मसले पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जा रही है। जल्द ही समस्या का समाधान तलाश लिया जाएगा। उन्होंने धरोपा क्लिनग गोपी में

शौघ ही मसूरी में वन भूमि सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे मसूरी वासियों को वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ मिल सकेगा।

उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थआन संरक्षण समिति के तत्वावधान में मंगलवार को नगरपालिका सभागार में आयोजित कामरेड वीरेंद्र भण्डारी श्रद्धांजलि सभा एवं पर्यटन-

महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अब मिशन शक्ति के तीसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां भी ग्राम सचिवालय संचालित हो रहे हैं वहां एक महिला शक्ति बूथ का गठन होना चाहिए।

मिशन शक्ति फेज-3 में निर्भया-एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जनपद एक हजार महिलाओं का एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम व तीन दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। इस दौरान 75 हजार महिलाओं को लाभांशित करने की योजना है। ओडीओपी उत्पाद के संबंध में भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक ही दिन व समय में प्रदेश के 75 विशेष लिफाफे जारी किए गए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश में महिला पिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में



उन्होंने बताया कि सिकरीगंज के महदेवा बाजार निवासी चंदन सैनी, राणा प्रताप चंद व धनंजय त्रिपाठी से उनका परिचय हुआ तो लगा कि नये दोस्तों से मिलने के बहाने गोरखपुर जाना भी हो जाएगा और बदलते गोरखपुर को भी देख लेंगे।

उन्होंने बताया कि वह गुडगांव से सड़क मार्ग द्वारा गोरखपुर आये। यहां

आने के बाद होटल के कमरे में बहुत आराम भी नहीं किया। अपराह्न तीन बजे भोजन करने के बाद रामगढ़ताल का भव्य नजारा देखा और मंगलवार को उनकी तैयारी थी गोरखनाथ मंदिर व गोरखपुर चिड़ियाघर देखने की, लेकिन रात में उनके साथ जो हुआ, उसके

बाद उनकी हिममत ही नहीं पड़ रही है कि वह जीवन में कभी अब इसे देख भी सकेंगे।

हमें तो फोन पर ही लग गया था कुछ गड़बड़ है- चंदन सैनी का कहना है कि मनीष उनके अच्छे जेहन वाले थे। रात करीब 12.13 बजे उनके चौकीचंदांच अक्षय मिश्रा

मेट्रो से उठा पर्दा, पूजन के बाद डिपो में ट्रैक पर उतारे गए कोच

कानपुर । लंबे इंतजार के बाद आखिर शहर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन से पर्दा उठ गया। गुजरात सजाली से आए सड़क मार्ग से सोमवार की रात कानपुर पालीटैक्निक डिपो में पहुंचे मेट्रो ट्रेन के कोच बुधवार को डिपो में उतारे गए। इससे पहले यहां पर मौजूद मेट्रो एमडी कुमार केशव ने कोच का पूजन अर्चन किया और फिर मेट्रो ट्रेन की असेंबलिंग का काम शुरू किया गया।

मेट्रो के तीनों कोच मंगलवार सुबह पालीटैक्निक डिपो पहुंचे थे। मंगलवार को पूरे दिन तीनों कोच प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर ही खड़े रहे। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टर कानुपुर मेट्रो की शुरुआत जल्द से जल्द करने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह साढ़े चार बजे गुजरात के सावली से मेट्रो कोच पालीटैक्निक डिपो में पहुंचे थे। फिलहाल मंगलवार को उन्हें ट्रेलर से उतारा नहीं गया और

ना ही इनके कवर हटाए गए हैं। बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक केशव कुमार डिपो पहुंचे। उनके सामने ही कवर हटया गया और उन्होंने डिपो में प्रोजेक्ट निदेशक के ऑफिस के सामने खड़े ट्रेलर पर रखे कोच का पूजन किया।

इसके बाद टोहंग मशीन की मदद से कोच ट्रैक पर उतारे गए। टोहंग मशीन के जरिए तीनों कोच खींचकर कवर पर्यकों में ले जाया गया और यहां पर उनका असेंबलिंगका का काम शुरू हुआ। मेट्रो का टैक्निकल स्ट्राफ असेंबलिंग बाद उनकी टैड्युस्टिंग शुरू कर देगा।

जल्दी काम खत्म करने का दबाव - पहलीं मेट्रो के कोच शहर में आने के बाद अब उत्तर में मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों पर अपनी टाइम लाइन को लेकर काफी दबाव है। स्टेशनों पर सिविल और सिस्टम से जुड़े काम खत्म करने का प्रेशर है। इसमें उन्हें 15 नवंबर को पहला ट्रायल रन करना है, इसके बाद जनवरी में मेट्रो को चलाना है।

वहां करीब रात 2.15 बजे पुलिस मनीष को लेकर पहुंची। 12.35 पर चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया।
रात में ही मनीष ने अपने मित्र को किया था फोन- मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि रात में जब पुलिस होटल के कमरे पर पहुंची तो मनीष ने कानपुर के अपने एक मित्र दुर्गाश के पास फोन किया था और उन्हें बताया था कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हालांकि पुलिस ने बताया था कि मनीष सो रहे थे। उन्होंने शराब पी रखी थी। बिस्तर से उठते ही वह नीचे गिरे उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि जब वह नींद में थे तो उन्होंने अपने मित्र के पास फोन कहां से किया।

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बड़ी घोषणा, 53 लाख परिवारों का बकाया 1200 करोड़ रुपये का बिजली बिल भरेगी सरकार

चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने दो केबी तक के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया 1200 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से 53 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। यह बकाया राशि पंजाब सरकार पावरकाम को देगी। यह फैसला आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सीएम ने कहा कि 1500 रुपये फीस देना सरकार कनेक्शन के लिए ली जाती है। इसे भी पंजाब सरकार भरेगी।

सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनेगी। इसमें एक एग्जिडीओ भी शामिल होगा। इस काम में सरपंचों की भी मदद ली जाएगी। राज्य में ऐसे एक लाख लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं जिन्होंने ये बिल नहीं भरे हैं, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछला बकाया सरकार देगी और उन्हें मुफ्त कनेक्शन मिलेंगे।

रेत माफिया पर नकेल के संबंध में चन्नी ने कहा कि रेत माफिया के पुराने के नेक्सस को खत्म करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यह जल्द खत्म हो जाएगा। जलद पॉलिसी जारी होगी। बता दें, रेत माफिया को लेकर



सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी यह मामला उठाते रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा पर चन्नी ने कहा कि पार्टी प्रधान होता है वह हेड होता है। हेड को परिवार में बैठकर बात करनी होती है। मैंने आज भी सिद्धू से बात की है। पार्टी सुप्रिम होती है। आपकी जो गलतियां लग रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। चन्नी ने कहा कि परगत सिंह और कई मंत्री उनसे मिलने गए थे। इस्तीफा देना पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है। उनके साथ बात करेगी। पंजाब में कांग्रेस के प्रति माहौल बन रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हम स्पेशल प्रक्सिक्वर को टीम तैयार कर रहे हैं। यह हमारे लक्षित केंसों को स्टडी करेगी। उन्होंने कहा कि उनका कोई अहम नहीं है। बेअदबी मामले में पीछे नहीं हटेंगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ऐसे किसी मामले से पीछे नहीं हटेंगा।

गांधी अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित होगा गांधी मंदिर, 40 लाख का बजट जारी

नैनीताल । शहर के समीपवर्ती ताकुला गांव स्थित गांधी मंदिर अब गांधी अध्ययन केंद्र के रूप में भी पहचाना जाएगा। शासन ने पर्यटन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 40 लाख का बजट जारी कर दिया है। इस धनराशि से पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के लिए जुलाई माह इसे अध्ययन केंद्र के स्वरूप में विकसित करने को विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। साथ ही केंद्र में अभियंताखाना बनाने की भी योजना है। जिसमें है महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित कर रखा जाएगा।

आता दें कि 1929 में कुमाऊं दौरे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैनीताल पहुंचने के बाद शहर के समीपवर्ती ताकुला गांव में ठहरे थे। जहां उनके द्वारा एक भवन का शिलान्यास भी किया था। आजादी के बाद स्थानीय लोगों द्वारा इस भवन को गांधी मंदिर नाम दे दिया गया। मगर देख रेख के अभाव में यह भवन जीर्ण शीर्ण हो गया। जिसके जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन

की मांग की। पालिकाध्यक्ष अनुज थिलाल्डू में खेल मैदान के निर्माण में रास्ते के लिए आ रही अड़चन की दूर करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी कटकशा नसीम को निर्देश दिए।

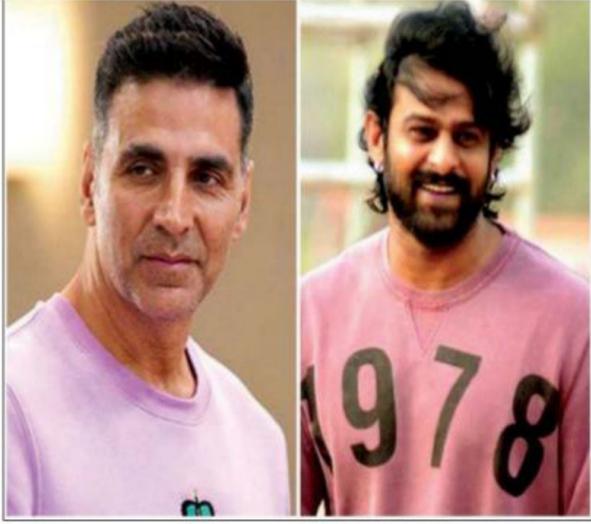
इससे पूर्व वक्ताओं ने प्रदेश में पर्यटन व इको पर्यटन के विकास के लिए पर्वतीय राज्य के अनुकूल नीति बनाने तथा वन अधिनियम 1००० में उन्नोचित संशोधन करने



कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कामरेड भण्डारी से भण्डारी विभाग के प्राध्याप मे

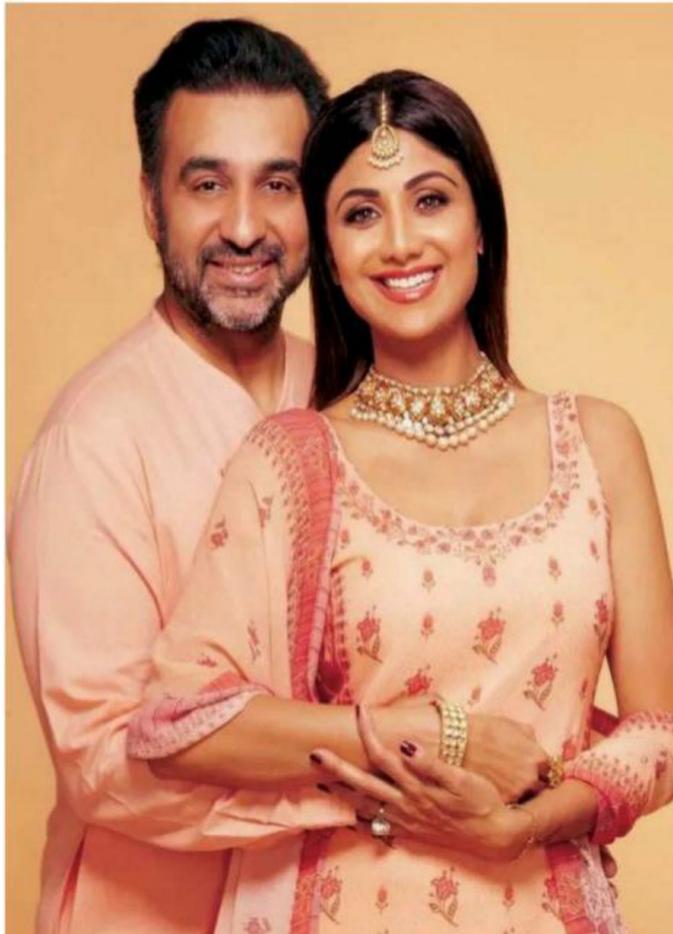
अर्पित किए। इस उन्होंने कामरेड भण्डारी की पत्नी सरस्वती भण्डारी को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।

गोष्ठी में हरक सिंह कहा कि स्वरोजगार के लिए कौशल विकास विभाग के प्राध्याप मे



2022 की बड़ी टक्कर, प्रभास और अक्षय कुमार की फिल्म होगी आमने-सामने

कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेलने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में भी सिनेमाघर दोबारा खोलने का ऐलान हो चुका है। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद से कई बिग बजट फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हो रहा है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में टकराने भी वाली है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कई अपकमिंग फिल्मों सूर्यवंशी, रक्षाबंधन और बच्चन पांडे की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। वहीं अब साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। वहीं आदिपुरुष की रिलीज डेट सामने आने के बाद दर्शकों को पर्दे पर अक्षय कुमार और प्रभास के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है। फिल्म आदिपुरुष स्वतंत्रता दिवस वाले सप्ताह में 11 अगस्त, 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की 'रक्षाबंधन' भी 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। स्वतंत्रता दिवस सप्ताह होने की वजह से फिल्म निर्माता इसका लाभ उठाना चाहते हैं। दोनों फिल्मों का बजट काफी बड़ा है। आदिपुरुष का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन का बजट भी करोड़ों में बताया जा रहा है। आदिपुरुष में प्रभास के साथ सैफ अली खान, कृति सेनन और सनी सिंह लीड रोल में हैं। ये फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। फिल्म रक्षाबंधन में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर अहम किरदार में हैं। रक्षा बंधन और आदिपुरुष साल 2022 की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस क्लैश में से एक होने वाली है। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष में प्रभास भगवान राम से प्रेरित किरदार में नजर आएंगे।



पति को लेकर मीडिया के सवालों पर भड़की शिल्पा शेट्टी, बोली- मैं राज कुंद्रा हूँ क्या?

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बीते कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी केस में गंभीर आरोप लगे थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि, अब वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी विवादों पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं और अपने काम में काफी बिजी हैं लेकिन हाल ही में वो मीडिया पर बुरी तरह नाराज होती तब दिखाई दी जब उनसे एक इवेंट पर राज कुंद्रा को लेकर सवाल पूछ लिया गया।

केस से कोई वास्ता नहीं

राज कुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हुई थी। उस दौरान पाया गया था कि इस केस से एक्ट्रेस का कोई वास्ता नहीं है लेकिन सोशल मीडिया से लेकर इवेंट्स तक शिल्पा से इस केस को लेकर उनसे सवाल किए जाने का सिलसिला कम नहीं हुआ। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट की मानें तो हाल ही में एक्ट्रेस से एक बार फिर से राज कुंद्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो एक्ट्रेस बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने सवाल पूछने वाले लोगों की क्लास लगा दी।

शिल्पा शेट्टी ने दिया जवाब

रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा- 'मैं राज कुंद्रा हूँ? मैं उसके जैसी लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं कौन हूँ?'... एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'मैं वाकई इस पर भरोसा करती हूँ कि एक सेलेब्रिटी के तौर पर आपको कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए ना कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। ये मेरी जिंदगी की फिलॉसिफी रही है'।

थलाइवी रिलीज के बाद कंगना ने दिखाए स्ट्रेच मार्क्स

अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस बारे में बात की है कि कैसे उनकी नवीनतम थलाइवी के लिए उनके वेट एडजस्टमेंट ने उनके शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा कर दी हैं, और उनके शरीर पर गहरे स्ट्रेच मार्क्स ला दिए हैं। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व अभिनेत्री जे जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म में उनकी भूमिका के लिए, कंगना को 20 किग्रा वजन बढ़ाना पड़ा और कई बार बड़े शारीरिक परिवर्तन से गुजरना पड़ा था। उन्होंने अपने अनुभव को इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसमें कंगना ने बताया कि छह महीने की अवधि में वह सब करने से उन्हें स्थायी स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं। उन्होंने लिखा कि 6 महीने में 20 किलो वजन बढ़ाना और 6 महीने में सब कम कर देना, वह भी तीस के दशक में मेरे शरीर में बहुत सी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, मेरे स्थायी स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ गए हैं, लेकिन कला एक कीमत के साथ जीवन में आती है।

थलाइवी में जयललिता के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें एक अभिनेत्री के रूप में उनकी कम उम्र में तमिल सिनेमा का चेहरा बनने के साथ-साथ राज्य की राजनीति के पाठ्यक्रम को बदलने वाले क्रांतिकारी नेता के उदय का पता चलता है। अपने आने वाले कामों की बात करें तो कंगना के पास फिलहाल धाकड़ है।

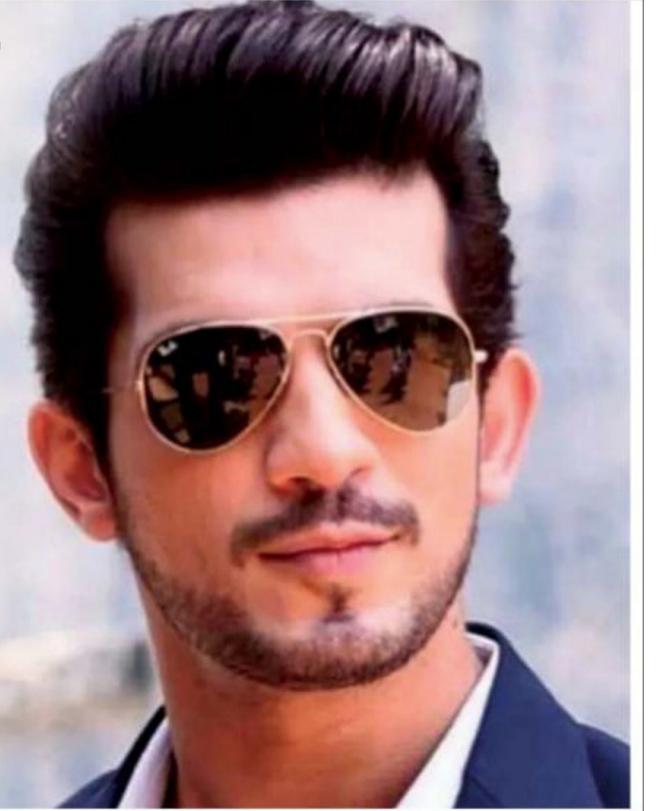
वह अपनी अगली फिल्म तेजस की भी शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वह एक फाइटर पायलट की भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लेती है। तेजस का निर्देशन नवोदित सर्वेश मेवाड़ा ने किया है। यह फिल्म आरएसवीपी की दूसरी फिल्म होगी जो जनवरी 2019 में रिलीज हुई बेहद सफल फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना को ट्रिब्यूट देती है।

अर्जुन बिजलानी ने जीता खतरों के खिलाड़ी, बेटे को समर्पित की ट्रॉफी

अभिनेता अर्जुन बिजलानी को रविवार को रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का विजेता घोषित किया गया। लोकप्रिय टीवी स्टार ने अपने पांच साल के बेटे अयान को शो की ट्रॉफी समर्पित की। अर्जुन ने टेलीविजन चैनल कलर्स पर प्रसारित हुए खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन में हिस्सा लिया था। शो को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में फिल्माया गया था।

अर्जुन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि वह शो जीतने के बाद बेहद खुश हैं क्योंकि इसमें हिस्सा लेना आसान काम नहीं था। अर्जुन (38) ने कहा, 'शो जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। केपटाउन में यह एक लंबा सफर था। जब रोहित सर ने विजेता के रूप में मेरे नाम की घोषणा की तो मैं बेहद खुश हुआ। मैं वास्तव में इसे अयान के लिए जीतना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि वह चाहता है कि मैं ट्रॉफी जीतूँ। एक बच्चे के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है।'

अर्जुन साथी कलाकारों दिव्यका त्रिपाठी, श्वेता तिवारी, विशाल आदित्य सिंह, गायक राहुल वैद्य और टीवी कलाकार वरुण सूद के अलावा शीर्ष छह फाइनलिस्ट में शामिल थे। अर्जुन 'नागिन', 'मेरी आशिकी तुम से ही', 'मिले जब हम तुम' और 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में दिखाई दे चुके हैं।



पूनम ढिल्लन और पद्मिनी कोल्हापुरी का ऋषि कपूर पर खुलासा, कहा- रोमांटिक सीन करना होता था मुश्किल

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के निधन को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन आज भी उनके किस्से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब हाल में पूनम ढिल्लन और पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर से जुड़े एक किस्से का खुलासा किया है। दरअसल यह दोनों एक्ट्रेसस सुपर डान्स चैप्टर 4 में पहुंची थी जहां उन्होंने ऋषि कपूर को याद करते हुए उनसे जुड़ा किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक सीन करना बहुत मुश्किल होता था।

उन्होंने बताया कि ऋषि खुद तो अपना सीन कैमरे के सामने बहुत अच्छे से शूट कर लिया करते थे लेकिन एक्ट्रेसस की बारी आने पर वह ऐसी हरकतें करते थे कि उन्हें हंसी आ जाती थी। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लन ने इस बात का खुलासा एक कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए किया और इस बात पर पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी अपनी सहमति जताई। ऋषि कपूर को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था। ऋषि कपूर का निधन पिछले साल हुआ था। एक्टर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। जिसका इलाज करवाने के लिए वह न्यूयॉर्क भी रहे। जहां से वह ठीक भी हुए थे लेकिन पिछले साल उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली।



31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद कपूर की जर्सी

अभिनेता शाहिद कपूर ने रविवार को इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म जर्सी की रिलीज डेट की घोषणा की। यह फिल्म 31 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता ने फिल्म से एक स्टिल अपलोड किया और इसे कैप्शन दिया, जर्सी 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है। यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तेलुगु फिल्म जर्सी की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। मूल फिल्म में अभिनेता नानी ने अभिनय किया था। दोनों फिल्मों का निर्देशन गौतम तिरुनुरी ने किया है। हिंदी रीमेक में शाहिद कपूर के साथ पंकज त्रिपाठी और अभिनेत्री मृणाल टाकुर भी हैं।



